हिंदी दैनिक

कलम की पहल

PRGI NO. UAHIN/25/A1323

वर्ष : 02 अंक : 159 पृष्ठ : 08 मूल्य : 1 रूपए नैनीताल, शुक्रवार, 27 नवंबर, 2026

E-mail: kalamkipahaluk@gmail.com Website: kalamkipahal.com

US की टैरिफ चाल से 5 लाख नौकरियों पर खतरा, PM मोदी से जवाबी कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 25 फीसदी तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बाद भारत में भी जवाबी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। देश के व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेडिंग इंडस्ट्री (CTI) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के सामानों पर भी 25 फीसदी रिटैलिएटरी टैरिफ यानी जवाबी शुल्क लगाने की अपील की है।

CTI ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के इस कदम से 48 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के निर्यात पर असर पड़ सकता है और लगभग 5 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ के चेयरमैन बृजेश गोयल ने गुरुवार को एक वीडियो बयान में कहा, 'हम प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करते हैं कि वे अमेरिका पर 25 प्रतिशत का जवाबी शुल्क



लगाएं। उन्होंने बताया कि व्यापारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इसका असर फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीफूड, रत्न और आभूषण, चमड़ा, धातु और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित शुल्क से अमेरिकी खरीदारों के लिए भारतीय सामान महंगे हो सकते हैं, जिससे वे अपने ऑर्डर अन्य प्रतिस्पर्धी देशों को दे सकते हैं।

बृजेश गोयल ने यह सवाल भी उठाया कि जिन निर्यातकों ने पहले ही अमेरिका के लिए सामान भेज दिया है या जिनके ऑर्डर मिल चुके हैं, उन खेपों का क्या होगा? अगर नए टैरिफ लागू होते हैं तो पुराने ऑर्डर और रास्ते में मौजूद माल पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर कारोबारियों में चिंता है।

अमेरिका ने लगाया टैरिफ तो गुस्से में चीन, बोला- 'गलत कदम वापस लो, वरना करेंगे कार्रवाई'

नई दिल्ली। अमेरिका की ओर से नए टैरिफ लगाने के प्रस्ताव पर चीन ने कड़ा विरोध जताया है. चीन ने गुरुवार को अमेरिका से अपनी गलत नीतियों को सुधारने और प्रस्तावित शुल्क लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा. साथ ही चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर चीन अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता हे यादोंग ने कहा कि अमेरिका की ओर से की जा रही जांच एकतरफा कार्रवाई है और चीन इसका दृढ़ता से विरोध करता है. उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनी गलत प्रथाओं को सुधारना चाहिए और बातचीत तथा आपसी परामर्श के जरिए विवादों का समाधान करने के सही रास्ते पर लौटना चाहिए.

दरअसल, अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ और जापान समेत कई व्यापारिक साझेदारों पर 20 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है. चीन उन देशों और अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, जिन पर सबसे अधिक 20 फीसदी शुल्क लगाने की बात कही गई है. इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने की आशंका है.

अमित शाह का विपक्ष पर बड़ा हमला

जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूम रहे, वे...

नई दिल्ली। संविधान दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जो लोग हाथ में संविधान लेकर घूम रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वे 15 मिनट संसद की लाइब्रेरी में जाकर संविधान को पढ़ें. उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने संविधान गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया जिस से इसकी भावना लोगों तक पहुंचे.

उन्होंने कहा, 'संविधान का सम्मान करना हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गर्व की जिम्मेदारी है. हालांकि, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के बाद संविधान को केवल सरकार चलाने की एक किताब मानने की कोशिश की गई. देश के किशोरों, युवाओं, नागरिकों में इसकी भावना को बैठाने और मजबूत करने की प्रक्रिया को भुला दिया गया. जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो 2015 में



उन्होंने निर्णय लिया कि हर साल 26 नवंबर को 'संविधान गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हमारे संविधान के सर्वोच्च मूल्यों को हर स्कूल, कॉलेज और सभी नागरिकों तक पहुंचाया जा सके. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'संविधान गौरव दिवस' के कार्यक्रम में कहा कि संविधान नागरिकों को यह तय करने का अधिकार देता है कि वे कैसे शासित होना चाहते हैं, जबकि सत्ता में बैठे लोगों को संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर शासन करने का निर्देश देता है.

उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि 80 सालों में हमारे देश के लोगों ने यह साबित कर दिया है कि भले ही संविधान ने 1949 में लोकतंत्र का ढांचा दिया, लेकिन इस देश की सभ्यता ने हजारों सालों से लोकतांत्रिक मूल्यों को संजोया है, जो अब संविधान के अनुच्छेदों के जरिए सामने आ रहे हैं.

उन्होंने कहा, 'इन 80 सालों में हमारे संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, शासन व्यवस्था और लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है. दोस्तों, हालांकि संविधान का सम्मान करने के दो तरीके हैं.

चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक जैसे पैकेटबंद फूड पर अब अलग से 'लाल' चेतावनी; बच्चों की सेहत को लेकर SC सख्त

नई दिल्लीः पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री और उपभोक्ताओं की सेहत से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को निर्देश दिया है कि हाई फैट, हाई शुगर और हाई साल्ट वाले खाद्य उत्पादों पर स्पष्ट चेतावनी लेबल लगाए जाएं. कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी आसानी से समझ में आनी चाहिए. इसके साथ ही बच्चों में पोषण जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया गया है. जस्टिस जे.बी.



पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग (FOPNL) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए. अदालत ने कहा कि जिन खाद्य उत्पादों में फैट, शुगर या नमक की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक है, उनके पैकेट के सामने लाल रंग का अलग-अलग हेक्सागोन चेतावनी चिन्ह लगाया जाए.

पीठ ने कहा कि यदि किसी उत्पाद में एक से अधिक पोषक तत्व तय सीमा से अधिक हैं तो प्रत्येक के लिए अलग चेतावनी चिन्ह अनिवार्य होगा. एक ही चेतावनी चिन्ह में कई पोषक तत्वों की जानकारी देना पर्याप्त नहीं माना जाएगा.

अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (लेबलिंग एंड डिस्प्ले) रेगुलेशंस, 2020 सहित खाद्य लेबलिंग से जुड़े मौजूदा नियमों को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए.

कोर्ट का मानना है कि सही और स्पष्ट सूचना मिलने से उपभोक्ता बेहतर निर्णय ले सकेंगे और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को समझ पाएंगे. बच्चों में पोषण जागरूकता बढ़ाने पर जोर

अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका से SC ने मांगा जवाब, CJI सूर्यकांत की बेंच का नोटिस

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका को सुप्रीम कोर्ट से एक और नोटिस मिल गया है। सीजेपी नेताओं को अब देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने उस याचिका पर जवाब देना है जिसे एक वकील संगठन ने दायर किया है और सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों के नियम-कायदे तैयार करने के निर्देश का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है। भारत के प्रधान जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने केंद्र



सरकार, सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य को नोटिस जारी करके उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है। वकील संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए। वकीलों के संगठन 'लॉयर्स वॉयस' ने इस याचिका में सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शनों के आयोजकों और उनमें भाग लेने वालों की जिम्मेदारियां तय करने के लिए व्यापक, एकसमान और प्रभावी दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

दीपके, सौरभ और रांका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी, देश नहीं छोड़ सकते

मुंबई पुलिस ने CJP के अध्यक्ष अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया. पुलिस के मुताबिक इन तीनों ने गांधी जयंती के दिन मुंबई में बिना पूर्व अनुमति के आंदोलन किया था. इस मामले में मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. अब पुलिस इनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया है ताकि वे देश छोड़कर बाहर न जा सकें.

EC ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CEO से SSR के बीच वोटर डिटेल्स को SIR डेटा से क्रॉस-चेक करने को कहा

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने बुधवार को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन (स्स्क्र) के दौरान वोटर रोल में किसी भी गलत या त्रुटिपूर्ण एंट्री की पहचान करें और उसे ठीक करें. इसके लिए मौजूदा चुनावी जानकारी की तुलना वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी से करें. चुनाव आयोग ने यह निर्देश अंडमान और निकोबार आइलैंड, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर,



पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, कर्नाटक और मेघालय के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को जारी किया है. इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी अपने पत्र में चुनाव आयोग ने इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 जनवरी, 2027 को पात्रता की तारीख मानते हुए मतदाता सूचियों की एसएसआर के संचालन के संबंध में अपने 15 अक्टूबर, 4 नवंबर और 16 अक्टूबर के पत्रों का उल्लेख किया है. चल रहे एसएसआर के दौरान मौजूदा वोटर रोल में वोटरों की जानकारी (जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम या टाइप, जन्म की तारीख, मोबाइल नंबर, फोटो) में किसी भी संभावित गलत या त्रुटिपूर्ण एंट्री की पहचान करने और उसे ठीक करने के लिए, संबंधित वोटरों की मौजूदा जानकारी की तुलना एसआईआर के दौरान इकट्ठा की गई संबंधित जानकारी से की जाएगी. चुनाव आयोग की तरफ से जारी लेटर में कहा गया है, 'जहां भी कोई मिसमैच दिखेगा, उसे वेरिफिकेशन और जरूरी सुधार के लिए चिह्नित किया जाएगा.' ऐसी चिह्नित की गई एंट्री के बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) चल रहे एसएसआर के दौरान संबंधित वोटरों के पास जाकर उनकी डिटेल्स वेरिफाई करेंगे और जहाँ भी जरूरत हो, ठीक से भरा हुआ और साइन किया हुआ फ़ॉर्म-8 लेंगे.

मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी, अमिताभ बच्चन के जलसा को भी उड़ाने की धमकी

मुंबई। मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है. धमरी भरे ई-मेल में कई सरकारी ऑफिसों के साथ-साथ अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं. मुंबई के मेयर ऑफिस को धमकी भरा ई-मेल मिला है. कुछ दिनों पहले टाइगर श्रॉफ पर हमला करने वाले गैंगस्?टर्स ने बताया था कि उनके निशाने पर अमिताभ बच्चन भी थे. इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. ई-मेल में अमिताभ बच्चन के अलावा दिलजीत दोसांझ का भी जिक्र किया गया है.

महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर हलचल, जल्द बुलाया जा सकता है संसद सत्र

नई दिल्ली। महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल को संसद से पास कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का फायदा दिलाने के लिए सरकार की कोशिश है कि इन दोनों बिलों को को जल्द से जल्द संसद से पास करवाया जाए.

इसको लेकर राजनीतिक और संसदीय स्तर पर हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कराने की है. वैसे तो संसद ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन



अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था. हालांकि, इस कानून के तहत आरक्षण तत्काल लागू नहीं होना है. संविधान के अनुच्छेद 334 के मुताबिक, इसके लिए संबंधित जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है.

चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में खुदकुशी, जम्मू के आर्यन की डेड बॉडी मिली, दरवाजा तोड़कर निकाली गई लाश

चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर-5 में गुरुवार को यूआईईटी (यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) के प्रथम वर्ष के एक छात्र ने कमरे में आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान जम्मू निवासी आर्यन के रूप में हुई है. वह हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर स्थित कमरे में रहता था. घटना का पता दोपहर करीब 1:45 बजे उस समय चला, जब उसका रूममेट वापस कमरे में पहुंचा. काफी देर तक दरवाजा खटखटाने



के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने हॉस्टल के गार्ड की मदद से दरवाजा खुलवाया. अंदर आर्यन की लाश पड़ी हुई थी.

आर्यन बुधवार देर रात हॉस्टल लौटा था. गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे उसका रूममेट कमरे से बाहर चला गया. दोपहर करीब 1:45 बजे जब वह वापस लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने गार्ड को बुलाया. इसके बाद दोनों ने दरवाजे को धक्का देकर खोला. दरवाजा खुलते ही कमरे के अंदर आर्यन की लाश मिली. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पहाड़ी पर दीप न जलने पर विवाद: SC में माफी, गर्वनर ने मांगी रिपोर्ट, अब आगे क्या?

नई दिल्ली। तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी स्थित दीपाथून स्तंभ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्तिगई दीप न जलाए जाने के मामले में मदुरै जिला प्रशासन ने मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है. 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समारोह के लिए 'दीपाथून' (पत्थर के खंभे) तक केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) द्वारा अधिकृत टीम ही सरकारी अधिकारियों के साथ जा सकती है. इस टीम में कौन-कौन शामिल होगा, यह तय करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की थी, जिन्हें मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस



आयुक्त के साथ परामर्श करना था. मंगलवार को TVK सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की. वार्षिक 'कार्तिगई दीपम' का आयोजन तिरुप्परनकुंद्रम में केवल पारंपरिक 'उचि पिल्लयार मंडपम' में किया गया, जबकि कोर्ट ने इसे पहाड़ी पर स्थित पत्थर के खंभे पर आयोजित करने का निर्देश दिया था. बता दें कि उच्ची पिल्लयार दीपा मंडपम और दीपाथून पत्थर के स्तंभ के बीच कोई सार्वजनिक सड़क नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही पहाड़ी पर पैदल चढ़ाई के रास्ते पर अलग-अलग ऊंचाई पर स्थित हैं. तिरुपरनकुंद्रम में 'दीपाथून' पर पारंपरिक दीपक न जलाए जाने के बाद तनाव फैल गया, जिसके चलते बीजेपी और हिंदू मुन्ननी के पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. 1978 में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाह बानो बेगम ने अपने पति द्वारा तलाक दिये जाने के बाद भरण-पोषण की मांग की. कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने रूढ़िवादी मुस्लिम समूहों के विरोध के चलते मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया. इस अधिनियम के चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला कमजोर हो गया. बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और चुनौती देता हूं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपने देव दीपावली के दिन 'कार्तिगई दीपम' के लिए दीपक जलाने की अनुमति नहीं दी. क्या कांग्रेस पार्टी या INDI गठबंधन में इतनी हिम्मत है कि वे किसी दूसरे धर्म के त्योहार पर बिना किसी कोर्ट के आदेश के (सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो दूर की बात है) ऐसी चीजों को रोक सकें? उन्होंने कहा कि ये सब INDIA गठबंधन की खतरनाक विचारधारा और सनातन धर्म को खत्म करने की उनकी चाहत का नतीजा है, जो 'डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व' (Dismantling Global Hindutva) नामक एक अंतरराष्ट्रीय साजिश से जुड़ी है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मदुरै में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के ऊपर स्थित पत्थर के खंभे पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है.

संविधान दिवस पर विधिक जागरूकता गोष्ठी आयोजित, पांच वरिष्ठ अधिवक्ता सम्मानित

के.के.पी संवाददाता

संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को अभियोजन विभाग की ओर से विकास भवन सभागार में विधिक जागरूकता गोष्ठी एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के सात महत्वपूर्ण अधिनियमों के उद्देश्यों, प्रावधानों और उनके व्यावहारिक महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर विधिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जनपद के पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं को स्मृति चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने कहा कि संविधान दिवस हमें संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने



का अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक नागरिक को देश के कानूनों और उनमें समय-समय पर होने वाले संशोधनों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि कानूनों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्यशालाओं एवं परिचर्चाओं का नियमित आयोजन आवश्यक है। उन्होंने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वालों का आभार व्यक्त किया। गोष्ठी में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024, भू-कानून संशोधन अधिनियम, 2025, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2024, प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2023, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2025, धर्म स्वतंत्रता कानून तथा उत्तराखंड देवभूमि परिवार अधिनियम, 2026 के विभिन्न प्रावधानों पर परिचर्चा की गई। सहायक निदेशक अभियोजन श्रद्धा रावत ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम, नकल विरोधी कानून और धर्म स्वतंत्रता कानून के उद्देश्यों, दंडात्मक प्रावधानों एवं कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोविंद बल्लभ उपाध्याय ने समान नागरिक संहिता, अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने देवभूमि परिवार अधिनियम तथा जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) वसंत बल्लभ पाठक ने भू-कानून संशोधन अधिनियम के प्रावधानों और उनके सामाजिक एवं कानूनी महत्व पर प्रकाश डाला।

28 नवंबर को जनपद में नौ स्थानों पर होगा आपदा मॉक अभ्यास, तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश

के.के.पी संवाददाता



28 नवंबर को जनपद में आयोजित होने वाले आपदा मॉक अभ्यास की तैयारियों को लेकर अपर जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह बिष्ट ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मॉक अभ्यास के सफल एवं प्रभावी संचालन के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अपर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉक अभ्यास के लिए निर्धारित घटनास्थलों एवं आपदा की परिस्थितियों के अनुरूप सभी तैयारियां समय से पूर्ण कर ली जाएं। इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण एवं वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रत्येक तहसील में गठित त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ ही एनसीसी, एनएसएस, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, आपदा मित्रों, स्वयंसेवकों एवं स्थानीय जनसमुदाय को भी अभ्यास में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक घटनास्थल पर लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था करने तथा संचार व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए वायरलेस सेट एवं सैटेलाइट फोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के निर्देश भी दिए।

जनपद में 28 नवंबर को नौ स्थानों पर आपदा प्रबंधन के तहत मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से भारी बारिश, जलभराव, शॉर्ट सर्किट, भूस्खलन, मानव-वन्यजीव संघर्ष, बादल फटने, भूकंप एवं अतिवृष्टि जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया एवं विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की परख की जाएगी। बैठक में उप जिलाधिकारी प्रियंका रानी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एक नजर

रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा में कुलपति प्रो. प्रवीण सिंह बिष्ट और स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज के बीच हुई वार्ता



के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। रामकृष्ण कुटीर, अल्मोड़ा में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रवीण सिंह बिष्ट और कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज के बीच स्वामी विवेकानन्द केंद्र, स्वामी विवेकानन्द से जुड़े स्थानों को लेकर विस्तार से वार्ता हुई। कुलपति ने कहा कि स्वामी जी के द्वारा स्पर्शित स्थानों को लेकर भविष्य में कार्यक्रम कुटीर के सहयोग से आयोजित होंगे। इस दौरान स्वामी की यात्रा, आध्यात्मिक यात्राएं, रामकृष्ण कुटीर, स्वामी से जुड़े पाठ्यक्रम के संचालन, सेमिनारों के आयोजन आदि पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इस अवसर पर स्वामी विवेकानन्द-महात्मा गांधी आध्यात्मिक पर्यटन परिपथ अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉ. चन्द्र प्रकाश फुलोरिया और सह संयोजक डॉ. ललित चन्द्र जोशी, श्री असीम पॉल, स्वामी मायाधीशानंद महाराज, अमन कुमार सहित कुटीर के सदस्य उपस्थित रहे।

संविधान की विकास यात्रा और अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर हुई चर्चा

के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना परिसर के इतिहास विभाग में संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संविधान की विकास यात्रा, सामाजिक समानता और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों तथा वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य वक्ता डॉ. गोकुल सिंह देउपा ने भारतीय संविधान के क्रमिक विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के कठिन संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान में निहित समानता के सिद्धांत की महत्ता बताते हुए कहा कि आज डॉ. अंबेडकर के जीवन और विचारों से निरंतर सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आत्ममंथन करने का आह्वान किया कि जिस संघर्ष से देश को आजादी मिली, क्या हम वर्तमान में वास्तव में डॉ. अंबेडकर के दर्शन को जान और अपने जीवन में अपना पा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रवि कुमार ने किया। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक बताते हुए कहा कि वंचित वर्गों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तीकरण तथा समान कानून और समान अधिकार की अवधारणाओं के पीछे डॉ. अंबेडकर के दूरदर्शी विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने इन विचारों को संवैधानिक और कानूनी स्वरूप देकर देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। गोष्ठी में डॉ. लक्ष्मी वर्मा, डॉ. शालिनी पाठक, नीरज बिष्ट सहित इतिहास विभाग के छात्र-छात्राएं रेनू लटवाल, दीपा मेहरा, प्रियंका लटवाल, ललित लटवाल, विनय कुमार, अशोक कुमार, अरुण प्रसाद, आदित्य, अंजलि, दिव्या, रिचा, शोभा, निशा, प्रियंका, अंबिका, सुजल, दीपक, हिमांशु, मोनिका आदि उपस्थित रहे।

राजकीय डिग्री कॉलेज पाटी में मनाया गया संविधान दिवस, युवाओं को दिया नशा मुक्त भारत का संदेश

भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, स्पोर्ट्स आइकन और यूथ आइकन ने साझा किए अनुभव

के.के.पी संवाददाता

चम्पावत। 26 नवंबर 2026 को माय भारत (MY Bharat), युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में माय भारत के उप निदेशक शैलेश भट्ट के मार्गदर्शन में राजकीय डिग्री कॉलेज पाटी में नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट (Neighbourhood Youth Parliament) और विकसित भारत युवा संवाद (Viksit Bharat Yuva Samvad) कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकसित भारत युवा संवाद के तहत संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉ. विभा पांडे और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.के. पांडे रहे। इस अवसर पर भारतीय संविधान की



प्रस्तावना, संवैधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कोमल, पूजा और कोमल ने बेहतर प्रदर्शन किया।

नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट के अंतर्गत नशा मुक्त भारत अभियान के तहत युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया और नशा मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में स्पोर्ट्स आइकन प्रीति ने अपनी खेल यात्रा साझा करते हुए बताया कि उन्होंने निरंतर मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाई। यूथ आइकन चंद्रवेश जुकिया ने अपने अनुभव साझा कर युवाओं को लक्ष्य निर्धारित करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉ. गीता तिवारी पांडे, प्रमोद वर्मा, डॉ. के.के. मिश्रा सहित अन्य शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में संवैधानिक जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी, नशा मुक्त जीवनशैली और राष्ट्र निर्माण के प्रति सहभागिता की भावना विकसित करना रहा।

साइंस सेंटर का निर्माण अंतिम चरण में, तीन भवन तैयार



के.के.पी संवाददाता

चंपावत। जिले में निर्माणाधीन साइंस सेंटर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। परिसर में साइंस कैंप फैसिलिटी, कैफेटेरिया और ऑडिटोरियम भवन का निर्माण पूरा हो चुका है। अब विज्ञान गैलरी में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और प्रदर्शनी मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हितेश कांडपाल ने साइंस सेंटर का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति परखी। उन्होंने ठेकेदार को शेष कार्य जल्द पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। साथ ही यूकॉस्ट के प्रतिनिधियों से वार्ता कर विज्ञान गैलरी में एक्जीबिट स्थापित करने का काम भी शीघ्र पूरा करने को कहा।

27 साल बाद फौजी चंद्रशेखर बगोली को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में जगह, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

1998 में सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भाजपा से जुड़े, फोर्ती गांव के दो बार रहे ग्राम प्रधान

के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट। निकटवर्ती फोर्ती गांव के फौजी चंद्रशेखर बगोली को भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया है। चंद्रशेखर वर्ष 1998 में सेना से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद वे भाजपा की राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए और सामाजिक कार्यों से जुड़ गए। उन्होंने भाजपा संगठन को मजबूत करने का काम शुरू किया। कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्होंने जनसेवा के उद्देश्य से ही भाजपा का दामन थामा था और बदले में उनकी कोई अपेक्षा नहीं थी।

अपने गांव के लोगों की सेवा करते हुए फोर्ती गांव के लोगों ने उन्हें दो बार ग्राम प्रधान चुना। उनके बेटे संदीप बगोली भी समाज सेवा के कार्यों में परछाई की तरह पिता का हाथ बंटाते रहे। एबीवीपी से जुड़े संदीप की



सेवाओं को देखते हुए स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज के छात्रों ने उन्हें छात्र संघ अध्यक्ष बनाकर सम्मानित किया।

चंद्रशेखर को प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किए जाने का पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि एक निस्वार्थ जनसेवक को पार्टी द्वारा दिया गया यह सम्मान सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है।

बगोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेता मिले हैं, जिनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री धामी देवभूमि के देवत्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके हाथ मजबूत करने की हम सबकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।

लोहाघाट में सहकारिता विभाग का वृहद किसान ऋण वितरण मेला, 56 काश्तकारों को 51 लाख रुपये के चेक वितरित

दुधारू पशु के लिए 30 लाख और कृषि ऋण के लिए 15 लाख रुपये दिए गए, काश्तकारों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई

के.के.पी संवाददाता

लोहाघाट। लोहाघाट विकासखंड के सभागार में आज 26 नवंबर 2026 को सहकारिता विभाग की ओर से वृहद किसान ऋण वितरण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड चानमारी की अध्यक्ष ममता देव ने की। संचालन भय्यू बोहरा और बलवंत गिरी ने किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार के पर्यटन विकास बोर्ड के सलाहकार (राज्य मंत्री स्तर) सुभाष बगौली रहे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंद्रशेखर बगौली, बैंक प्रतिनिधि देवेंद्र पाटनी और खंड विकास अधिकारी कविंद्र सिंह रावत मौजूद रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सभागार में उपस्थित काश्तकारों को संचालक भय्यू बोहरा ने संविधान दिवस की शपथ दिलाई।

अपर जिला सहकारी अधिकारी कमला



मेहरा ने सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी काश्तकारों को दी। उप महाप्रबंधक संजीव कुमार, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ममता नेगी, सहायक विकास अधिकारी हेमा घुघत्याल और समिति परिषद संगठन चम्पावत के अध्यक्ष जगदीश जोशी ने अतिथियों का गुलदस्ता, अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने लोहाघाट विकासखंड की समस्त सहकारी समितियों के 56 काश्तकारों को कुल 51 लाख रुपये (इक्यावन लाख रुपये) के चेक वितरित किए। इनमें सिद्ध बाबा स्वयं सहायता समूह बरगोली को डुमडाई समिति ने 3 लाख रुपये और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की लोहाघाट शाखा ने 3 लाख रुपये व्यक्तिगत रूप में दिए। 30 लाख रुपये दुधारू पशु और 15 लाख रुपये कृषि ऋण के लिए दिए गए। अतिथियों ने सहकारिता विभाग की योजनाओं की सराहना करते हुए काश्तकारों को इनका अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर खेतेड़ा सहकारी समिति की अध्यक्ष सरिता अधिकारी, धरमघर सहकारी समिति की अध्यक्ष हेमा राय, डुमडाई सहकारी समिति के अध्यक्ष शंकर दत्त पांडेय, दिगालीचौड़ सहकारी समिति के अध्यक्ष जोगा राम और पूर्व ग्राम प्रधान गंगनौला ललित मोहन जोशी, गिरीश कुंवर सहित कई लोग उपस्थित रहे। सहयोग के लिए सहकारी समितियों के कर्मचारी नीरज कुमार, जीवन लाल, दिनेश नाथ गोस्वामी, भुवन कुमार, गणेश सामंत, योगिता पंत, किशन बोहरा, सुरेश कुंवर, निर्मल भट्ट, रतन राम और जगदीश जोशी भी मौजूद रहे। अंत में अध्यक्षता कर रही ममता देव ने सभी अतिथियों और काश्तकारों का स्वागत कर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, सितारगंज, उधम सिंह नगर

पत्रांक 1640/ निविदा/ वी०पी०-जीराम /2026-27 दिनांक 26/11/2026

निविदा

महामहिम राज्यपाल, महोदय उत्तराखण्ड शासन की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेरा गाँव मेरी सड़क/ वी०पी०-जीराम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत वर्ष 2026-27 के सापेक्ष सामग्री आपूर्ति हेतु जो कि राजकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों से सम्बन्धित निविदायें दिनांक 10.12.2026 अपराह्न 01 बजे तक खण्ड विकास अधिकारी सितारगंज के कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन निविदादाताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खण्ड विकास अधिकारी सितारगंज द्वारा अपने कार्यालय में अपराह्न 03 बजे खोली जायेगी। निविदाओं का क्रियान्वयन दिनांक 09.12.2026 तक विकास खण्ड कार्यालय के कार्यदिवस में किया जायेगा।

नोट-निर्माण कार्य में (मजदूरी) श्रमांश वी०पी०-जीराम श्रमिकों से कार्य कराया जायेगा।

क्र. सं.	कार्य का नाम	मेरा गाँव मेरी सड़क राज्य अंश लाख में	धरोहर धनराशि मेरा गाँव मेरी सड़क राज्य अंश	वी०पी०-जीराम जी सामग्री आपूर्ति धनराशि लाख में	वी०पी०-जीराम जी सामग्री आपूर्ति धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण की अवधि	निविदा की वैधता
1	ग्राम पंचायत बिज्टी में अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज होते हुए ग्राम कोठारतन को जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य।	24.605	0.50	18.685	0.38	6 माह	180 दिन
2	ग्राम पंचायत गोठा में मेन डामर रोड से ग्राम पण्डरी सीमा तक का मार्ग का निर्माण कार्य।	24.605	0.50	18.685	0.38	6 माह	180 दिन

1.कार्यादेश के साथ प्रत्येक कार्य हेतु अंकित अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत धनराशि धरोहर राशि एन०एस०सी०/ डाकघर बचत बैंक पासबुक के रूप में जो कि खण्ड विकास अधिकारी सितारगंज के पद नाम से बंधक हो जमा करनी होगी।

1 (क) उक्त कार्यों पर निविदा वी०पी०-जीराम जी अंश एवं वी०पी०-जीराम जी सामग्री आपूर्ति हेतु पृथक-पृथक आमंत्रित की जायेगी।

2. यदि कोई ठेकेदार निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगाना चाहता है तो वह निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं डाकखर्च व्यय समय से भेजकर प्राप्त कर सकता है।

3. निविदा प्रतिशत दरों में ही मान्य होगी।

4. कार्यादेश के साथ निविदादाता का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जी०एस०टी० प्रमाण पत्र, पैन कार्ड की छाया प्रति एवं धरोहर राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र (मूल रूप में संलग्न करने अनिवार्य हैं)।

5. सफल निविदादाताओं को अतिरिक्त धरोहर राशि के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

6. निविदा के साथ रु० 100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 1.00 के रसीदी टिकट के साथ ठेकेदार का हस्ताक्षरयुक्त होना होना चाहिए।

7. बिल भुगतान के समय नियमानुसार आयकर एवं जी०एस०टी० आदि की कटौती की जायेगी।8. अधोहस्ताक्षरी को किसी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।

9. अपूर्ण एवं शर्तों से निविदा किसी भी रूप में मान्य नहीं होगी।

10. निर्माण कार्य की गुणवत्ता विभिन्न स्तर की पायी जाती है या त्रुटिपूर्ण पाए जाने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान होने के कारण शासन को धनराशि की क्षति की स्थिति में वसूली शासनादेश संख्या 9899/23-999-11/96/लो.नि.वि. के अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 12 मई, 1999 के अनुसार (2) में निहित प्रावधानानुसार की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की रहेगी।

11. प्राविधिक परीक्षक (टी०ए०सी०) उत्तराखण्ड द्वारा निरीक्षण के उपरान्त कार्य में यदि कोई कमी या वसूली निकाली जाती है तो उसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का वहन करना होगा, आवश्यकता पड़ने पर टी०ए०सी० की जाँच के उपरान्त ही ठेकेदार की जमानत राशि वापस की जायेगी।

12. कार्य की अन्य शर्तें किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

13. कार्यालय पर 2.5X3 फिट में काम का सूचना फ्लेक्स अवश्य लगाया जायेगा।

14-निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फोटोग्राफ, कार्य के दौरान फोटोग्राफ लिया जाना आवश्यक होगा (तीनों फोटोग्राफ एक Angle से होने चाहिए)।

15-निविदा प्रपत्र मूल्य 2000.00+18 % GST वी०पी०-जीराम जी अंश

(क) निविदा प्रपत्र मूल्य 1500.00+18 % GST वी०पी०-जीराम जी अंश सामग्री आपूर्ति

खण्ड विकास अधिकारी,\सितारगंज (उधमसिंह नगर)।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं स्विट्जरलैंड के एफएफएचएस के मध्य शैक्षणिक सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समावेश पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित



के.के.पी संवाददाता/हल्द्वानी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी एवं स्विट्जरलैंड स्थित स्विस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज (स्नस्न॥स्) के मध्य शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों संस्थानों के मध्य अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग, ज्ञान एवं अनुभव के आदान-प्रदान तथा भविष्य में संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ द्वारा अंतरराष्ट्रीय अतिथि प्राध्यापक फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 'पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं विश्वविद्यालय के कुलगीत के गायन के साथ हुआ। कार्यक्रम का समन्वयन जितेंद्र पांडे ने किया। एफएफएचएस के प्रो. तोबियास हैबरलिन एवं अन्जा बूरों ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

स्वागत संबोधन प्रो. पी.डी. पंत ने दिया। उन्होंने कहा कि यह समझौता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रयासों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। उन्होंने पाठ्यक्रम विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते महत्व पर भी प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी ने स्विट्जरलैंड में टैगोर चेयर फेलोशिप के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड की शैक्षणिक गतिविधियों में गुणवत्ता और केंद्रित दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने डॉ. लुसिने मर्क्त्च्यान के विश्वविद्यालय प्रवास के दौरान उनके साथ कार्य करने के अनुभव को भी साझा किया। प्रो. लोहनी ने कहा कि यह एमओयू विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शिक्षण पद्धतियों को और सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में उच्च शिक्षा में हो रहे तकनीकी परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रियाओं को विकसित करना आवश्यक है, तथा विश्वविद्यालयों में तकनीकी नवाचार, शैक्षणिक उत्कृष्टता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इसके पश्चात कुलपति प्रो. नवीन चंद्र लोहनी एवं कुलसचिव ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर प्रो. तोबियास हैबरलिन ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण एमओयू है, जिससे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विशाल विद्यार्थी वर्ग को लाभ मिलेगा। अन्जा बूरों ने कहा कि यह समझौता शोध एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों को और समृद्ध करेगा। दोनों ने भविष्य में संबंधों को और प्रगाढ़ करने की आशा व्यक्त की।

इसके बाद मुख्य वक्ता डॉ. लुसिने मर्क्त्च्यान, विजिटिंग प्रोफेसर, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं स्विस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज (स्नस्न॥स्) ने संगोष्ठी में व्याख्यान दिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड की सबसे कम बेरोजगारी दर का उल्लेख करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण पर प्रकाश डाला।

किसानों को बड़ी राहत, फार्मर आईडी की अनिवार्यता हटने से खुशी की लहर

मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से किसानों को मिली राहत,

क्रय-विक्रय सहकारी समिति में मिठाई बांटकर मनाई खुशी

किसानों ने जताया आभार

कहा- खेती-किसानी से जुड़े कार्यों में नहीं होनी चाहिए अनावश्यक परेशानी



के.के.पी संवाददाता

सितारगंज,(दीपक भारद्वाज) किसानों के हित में फार्मर आईडी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के निर्णय से क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के प्रयासों से किसानों को मिली इस राहत पर क्षेत्र के किसानों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया। किसानों का कहना है कि फार्मर आईडी बनवाने की अनिवार्यता के चलते उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे किसान, जिन्हें इस प्रक्रिया की जानकारी जुटाने और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में परेशानी हो रही थी, वे काफी चिंतित थे। ऐसे में अनिवार्यता समाप्त होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है।

इस निर्णय की खुशी में क्रय-विक्रय सहकारी समिति सितारगंज के परिसर में किसानों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसान और जनप्रतिनिधि एकत्र हुए।

किसानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान किसानों में खासा उत्साह दिखाई दिया। किसानों ने कहा कि उनकी समस्या को गंभीरता से उठाते हुए मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सरकार के स्तर पर प्रयास किए, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

सांप काटने पर भागे नहीं, घबराहट पर रखे कंट्रोल



लंदन। जहरीला सांप अगर काट लें तो आपातकालीन स्थिति में हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। यदि अचानक कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो वहां से भागना ही सबसे बेहतर विकल्प है, लेकिन इस दौरान अपने भय पर काबू पाना जरूरी है। डर से कई बार लोगों का दिल का दौरा भी पड़ सकता है। लंबी गहरी सांस लें और हिम्मत बनाए रखें। अगर आप सही से भागेंगे तो सांप आपसे ज्यादा तेजी से नहीं चल पाएगा। हालांकि, सांप अक्सर छिपकर वार करता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह मायने रखता है। अगर सांप आपको काट ही ले, तो वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल न करें। विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से भागने पर सांप का जहर खून में और भी तेजी से फैलने लगता है, क्योंकि खून पूरे शरीर के अंगों में लगातार चलता रहता है। जब यह जहर हृदय, यकृत, गुर्दे और मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। सांप काटने के बाद सबसे पहला काम यह है कि आप आसपास किसी सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं और बिल्कुल शांत रहें। अपने डर को काबू करें और गहरी सांस लें। जितनी कम हलचल होगी, जहर को फैलने में उतना अधिक समय मिलेगा। यदि आपने तंग कपड़े, घड़ी या अंगूठी पहनी है तो उन्हें तुरंत उतार दें। जहां सांप ने काटा है, उस जगह को साबुन और पानी से साफ करने का प्रयास करें। इसके बाद उस जगह पर पट्टी बांधने की कोशिश करें। पट्टी बांधने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कसकर बिल्कुल न बांधें, क्योंकि इससे रक्त संचार रुक सकता है और वह अंग बेकार हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पट्टी को ऊपर से नीचे तक इस तरह से बांधें कि वह न तो बहुत टाइट हो और न ही बहुत ढीली। इससे लिम्फेटिक वैसल्स बंद हो जाएंगी, जो जहर को आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन आर्टरीज खुली रहेंगी, जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बना रहेगा। लिम्फेटिक वैसल्स महीन नलिकाएं होती हैं जिनमें द्रव भरा होता है; हलचल से इनके वॉल्व खुल जाते हैं और जहर तेजी से फैलता है।

अगर तत्काल पट्टी उपलब्ध न हो तो सूती तौलिया, धोती का टुकड़ा या किसी भी साफ, सूखे सूती कपड़े का इस्तेमाल करें। अपने बनियान को फाड़कर भी पट्टी बनाई जा सकती है। विशेषज्ञों ने कुछ बातों पर विशेष जोर दिया है जो सांप काटने पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिएः उस जगह पर बर्फ न लगाएं, घाव से छेड़छाड़ न करें, उसे दांत से काटने या खून निकालने की कोशिश न करें।

संविधान के प्रति निष्ठा और देश की एकता-अखंडता बनाए रखने की पुलिस कर्मियों ने ली शपथ

संविधान दिवस पर कोतवाली सितारगंज में हुआ कार्यक्रम,

अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया संवैधानिक मूल्यों के पालन का संकल्प



के.के.पी संवाददाता
सितारगंज,(दीपक भारद्वाज)

संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार 26 नवंबर को कोतवाली सितारगंज परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कोतवाली के समस्त थाना एवं चौकी स्टाफ को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों और कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करने का संकल्प लिया।

शपथ के दौरान सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, संवैधानिक आदर्शों का सम्मान करने तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर संविधान में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत आदर्शों के महत्व को भी रेखांकित किया गया। पुलिस कर्मियों को अपने कार्यों और व्यवहार में संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता देने तथा कानून के प्रति सम्मान बनाए रखने की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम के दौरान यह संकल्प भी दोहराया गया कि पुलिस विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और समाज में कानून व्यवस्था, शांति तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।

संविधान दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस कर्मियों ने लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

वन अधिकार संगठन की पहल लाई रंग, जिलाधिकारी ने बिंदुखत्ता की समस्याओं पर दिखाई तत्परता

के.के.पी संवाददाता



लालकुआं। बिंदुखत्ता की जनसमस्याओं को लेकर वन अधिकार संगठन के शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल से मुलाकात कर विभिन्न मांगों के समाधान हेतु ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी ने जनहित के मुद्दों पर गंभीरता दिखाते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। शिष्टमंडल ने गौला नदी में तटबंध निर्माण, किसानों को खाद उपलब्ध कराने, गन्ना किसानों को हल्द्वानी से जोड़ने तथा स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जारी करने की मांग प्रमुखता से उठाई।

खाद की समस्या पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए हल्दूचौड़ सहकारी समिति में बिंदुखत्ता के किसानों के लिए अतिरिक्त खाद उपलब्ध कराने तथा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर वितरण सुनिश्चित कराने को कहा। वहीं गन्ना किसानों को हल्द्वानी की समिति से जोड़ने और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

गौला नदी में तटबंध निर्माण की मांग पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं जाति एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्रों के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों के प्रमाण पत्र किसी भी हालत में नहीं रुकने चाहिए। पटवारियों की हड़ताल के बावजूद प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर पटवारी की रिपोर्ट के स्थान पर अमीन से रिपोर्ट लेकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वन अधिकार संगठन की इस सक्रिय पहल और जिलाधिकारी की त्वरित कार्यशैली से बिंदुखत्ता के लोगों में अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है। शिष्टमंडल में वन अधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट, वन अधिकार समिति के अध्यक्ष अर्जुन नाथ गोस्वामी, अधिवक्ता बलवंत सिंह बिष्ट , पूर्व सैनिक संगठन से कैप्टन इंद्र सिंह पनेरी, राजेन्द्र सिंह बिष्ट व गोविंद गिरी सहित आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल रहे।

सस्ते बाहरी दूध और पनीर की गुणवत्ता पर उठे सवाल, डीएम चलाएंगे विशेष मुहिम

लालकुआं। वन अधिकार संगठन के अध्यक्ष उमेश चंद्र भट्ट ने जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के समक्ष स्थानीय पशुपालकों की समस्या उठाते हुए कहा कि लालकुआं और हल्द्वानी के बाजारों में बाहर से आने वाला दूध एवं पनीर स्थानीय उत्पादों की तुलना में काफी सस्ते दामों पर बिक रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि इतनी कम कीमत पर बिकने वाले दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता संदिग्ध हो सकती है और उनमें मिलावट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इन उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता की जांच कराने की मांग की। इस पर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता व बिक्री को लेकर विशेष अभियान चलाने का आश्वासन दिया।

ग्रामीण युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए नाबार्ड ने शुरू किया अभियान

100 से अधिक युवाओं ने किया प्रतिभाग, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय योजनाओं की दी जानकारी

के.के.पी संवाददाता
सितारगंज (दीपक भारद्वाज)।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से नाबार्ड की ओर से राष्ट्रव्यापी ग्राम युवा शक्ति अभियान 2026 की शुरुआत की गई। बृहस्पतिवार को सितारगंज में आयोजित कार्यक्रम में 100 से अधिक ग्रामीण युवाओं, विद्यार्थियों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में युवाओं को कौशल विकास, उद्यम स्थापना और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) नाबार्ड अजय डी. नायक ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में ग्रामीण युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्यमिता, नवाचार और कौशल विकास के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर बनने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने मेरा युवा भारत (माई भारत) के सहयोग से यह अभियान शुरू किया है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के प्रति रुचि रखने वाले युवाओं की पहचान कर उनकी क्षमता और जरूरतों का आकलन किया जाएगा। इसके आधार पर उन्हें कौशल प्रशिक्षण, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और उद्यम स्थापित करने के लिए संबंधित संस्थाओं के माध्यम से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम में सहायक खंड विकास अधिकारी देशराज ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित आजीविका संवर्धन और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की जानकारी दी। अग्रणी जिला प्रबंधक कमल कुमार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कृषि अवसंरचना निधि, पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा और स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं के बारे में बताया।

बीओबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के फैकल्टी सुरेश कुमार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक मोहित कुमार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में बताया। वहीं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र के वरिष्ठ प्रबंधक इशु अस्थाना ने संस्थान की ओर से उपलब्ध प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग की जानकारी दी।

तिलियापुर का 51 साल पुराना भूमि विवाद फिर गरमाया, किसानों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

धौरा बांध की निष्प्रयोज्य भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग

तीसरी-चौथी पीढ़ी से खेती कर रहे भूमिहीन परिवारों ने कराई उच्चस्तरीय जांच की मांग

के.के.पी संवाददाता
सितारगंज(दीपक भारद्वाज)।

तिलियापुर गांव में धौरा बांध की निष्प्रयोज्य कृषि भूमि को लेकर 51 साल पुराना विवाद एक बार फिर गरमा गया है। दशकों से इस भूमि पर खेती कर रहे भूमिहीन किसान परिवारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। किसानों के अनुसार कुछ समय पूर्व उनकी काबिज कृषि भूमि पर सर्वे टीम पहुंची थी। इस दौरान जानकारी मिली कि बाजपुर क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिए वन विभाग की ली गई भूमि के बदले तिलियापुर की कृषि भूमि वन विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। किसानों ने सवाल उठाया है कि जब इस भूमि का हस्तांतरण वर्ष 1975 से ही लंबित है और इसका स्वामित्व एवं प्रबंधन सिंचाई विभाग के पास है तो दोबारा हस्तांतरण की कार्रवाई किस आधार पर की जा रही है। किसानों ने 29 मार्च 1975 के अर्द्धशासकीय पत्र का हवाला देते हुए बताया कि धौरा बांध की 299.87 हेक्टेयर निष्प्रयोज्य भूमि को सिंचाई विभाग से वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन करीब 51 साल बीतने के बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। वन विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में भी हस्तांतरण लंबित होने की बात स्वीकार की है। किसानों ने एक नवंबर 1975 को जारी शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि आठ नवंबर 1973 तक वन भूमि पर काबिज भूमिहीन खेतीहर मजदूर परिवारों के अतिक्रमण नियमित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के तहत भी 13 दिसंबर 2005 से पहले से खेती कर रहे पात्र परिवारों के अधिकारों पर विचार करने की मांग की गई है। पत्र में किसानों ने बताया कि संबंधित परिवारों को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, बिजली कनेक्शन और आधार कार्ड सहित अन्य नागरिक सुविधाएं भी प्राप्त हैं। उन्होंने खसरा संख्या 114 में 7.5070 हेक्टेयर और खसरा संख्या 118 में 10.4360 हेक्टेयर भूमि का राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने का भी उल्लेख किया है। किसानों ने 149 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित करने और पुराने अतिक्रमणों के नियमितीकरण के उदाहरण देते हुए तिलियापुर के मामले में भी जनहित में निर्णय लेने की मांग की है। उनका सुझाव है कि सरकार पुराने हस्तांतरण संबंधी पत्र को निरस्त कर भूमि राजस्व विभाग को सौंपने की दिशा में कदम उठाए। मुख्यमंत्री को भेजे पत्र की प्रतिलिपि वन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, आयुक्त कुमाऊं मंडल, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर, उपजिलाधिकारी सितारगंज और संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी भेजी गई है। पत्र के साथ वर्ष 1975 के अर्द्धशासकीय पत्र, शासनादेश, वन विभाग से प्राप्त सूचना और खसरा-खतौनी की प्रतियां संलग्न की गई हैं।

सिंगापुर यात्राः हाई कमीशन की शर्तों का पालन न करने पर आ सकती है बाधाएं

भारतीय पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी अनिवार्य



सिंगापुर। सिंगापुर का पर्यटन क्षेत्र भारतीय यात्रियों के लिए खास है, जहां भारत की हिस्सेदारी लगभग 7.1फीसदी है। यह चीन और इंडोनेशिया के बाद सिंगापुर के पर्यटन में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। भारतीय नागरिकों के लिए सिंगापुर की यात्रा से पहले पासपोर्ट की वैधता, वीजा आवश्यकताओं और आगमन संबंधी नियमों की गहन जानकारी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इमिग्रेशन एंड चेक पॉइंट्स अथॉरिटी और सिंगापुर के हाई कमीशन द्वारा निर्धारित इन शर्तों का पालन न करने पर यात्रा में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। सबसे पहले, सिंगापुर पहुंचने की तय तिथि से आपके भारतीय पासपोर्ट की वैधता कम से कम 6 महीने होनी अनिवार्य है। यह एक गैर-परक्राम्य नियम है, यदि आपके पासपोर्ट की वैधता इससे कम है, तो एयरलाइंस आपको विमान में चढ़ने से रोक सकती है और सिंगापुर के इमिग्रेशन अधिकारी आपको देश में प्रवेश देने से इनकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आपका पासपोर्ट अच्छी स्थिति में होना चाहिए और उसमें दर्ज व्यक्तिगत जानकारी आपके वीजा और फ्लाइट टिकट से पूरी तरह मेल खानी चाहिए। इन बुनियादी नियमों की अनदेखी अप्रत्याशित कठिनाइयों का कारण बन सकती है। सिंगापुर वीजा के लिए सरकारी प्रोसेसिंग शुल्क 30 सिंगापुर डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में करीब 2100 रुपए के बराबर होता है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य है। भारतीय आवेदक किसी अधिकृत सिंगापुर वीजा एजेंट के जरिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें प्रति आवेदन 1300 रुपए तक का अतिरिक्त सेवा शुल्क लग सकता है। सिंगापुर में रहने वाले पात्र व्यक्ति सिंगपास या कॉर्पपास का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं। सामान्यतः, वीजा आवेदन प्रक्रिया में 3 से 5 कार्यदिवस लगते हैं, जिसमें आवेदन जमा करने का दिन, वीकेंड और सार्वजनिक छुट्टियां शामिल नहीं होतीं।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करें ताकि किसी भी संभावित देरी से बचा जा सके।

संपादकीय

यूपी 2027 विधानसभा चुनाव : धर्म और अधर्म का युद्ध या संविधान और सत्ता की लड़ाई

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। जिस तरह के राजनीतिक और सामाजिक हालात बन रहे हैं, उन्हें देखकर महाभारत के युद्ध की याद आना स्वाभाविक है। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता, अधिकार और धर्म की लड़ाई थी। युद्ध जीतने के लिए चक्रव्यूह रचे गए, अभिमन्यु को घेरकर मारा गया और धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से निकले आधे-अधूरे सत्य ने युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ ऐसे ही दांव-पेच दिखाई देने लगे हैं। हालांकि इस तुलना को राजनीतिक घटनाओं की वास्तविक स्थिति को देखते हुए तुलना के रूप में समझना चाहिए। धर्म और दूसरे को अधर्म का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है। उसका आरोप है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव आयोग पालन नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के पक्ष में काम कर रहा है, जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष विपक्ष की एकजुटता को चुनौती देने के लिए राजनीतिक रणनीतियां अपना रहा है। सवाल यह है कि क्या चुनाव जनता के वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाएगा या एक-दूसरे को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए नए चक्रव्यूह एवं साजिश रची जाएंगी? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए बनाया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति को चुनौती देने के लिए चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक सक्रियता उत्तर प्रदेश के चुनाव में नए समीकरण बना सकती है। मायावती की चुनावी सक्रियता भी इन समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। इन दलों और नेताओं को भाजपा की बी टीम बताने जैसे आरोप भी राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। ऐसे आरोपों का फैसला अंततः मतदाता अपने विवेक से करेगा। विपक्षी मतों का बंटवारा किसे लाभ पहुंचाएगा, यह इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

दूसरी ओर धार्मिक राजनीति का स्वर भी तेज होता दिखाई दे रहा है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के नाम पर राजनीतिक और धार्मिक विमर्श के बीच बाबा रामदेव और धीरेंद्र शास्त्री के विवाद ने एक नई बहस को जन्म दिया है। धर्म के नाम पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने, साधु-संतों और बाबाओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक टकराव दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण, चंदे को लेकर उठे विवाद, युवाओं के असंतोष और जेन-जी से जुड़े आंदोलनों के बीच हिंदुत्व कमजोर होता हुआ दिख रहा था। समाज के भीतर अलग-अलग विचारधाराएं, अलग-अलग आस्थाएं और हिंदुओं के कई समूह सक्रिय हैं। ऐसे वातावरण में धार्मिक भावनाओं का चुनावी इस्तेमाल हिंदुत्व की सामाजिक एकता के लिए चुनौती बन सकता है। इस पूरे राजनीतिक संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष संविधान है। भारत का लोकतंत्र किसी धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या या किसी राजनीतिक दल की इच्छा से नहीं, बल्कि संविधान और कानून से संचालित होता है। महाभारत में धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ था। वर्तमान में लोकतंत्र की रक्षा, आधुनिक भारत में संविधान के अनुसार न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार इस लड़ाई में शामिल हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता, मतदाता के मत का सम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थाओं की जवाबदेही लोकतंत्र के मूल आधार हैं। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा कि केंद्र में भविष्य में किसकी सरकार बनेगी। राजनीति, धर्म के नाम पर समाज को बांटेगी या संविधान के आधार पर सबको समान अधिकार देगी। लोकतंत्र में जनता ही निर्णायक होती है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को विजय तो मिली, लेकिन दोनों पक्षों ने अपनों को खोया। आज भारत को ऐसे चुनाव की जरूरत है, जिसमें जीत किसी भी दल या गठबंधन की हो लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो। इस चुनाव में लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और संवैधानिक मर्यादाओं की हार नहीं होनी चाहिए। असली धर्म सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि सत्ता का उपयोग जनकल्याण और न्याय के लिए करना है। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव का यही लक्ष्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होना चाहिए।

सावधान करियर से अधिक जरूरी है जिंदगी

मनोज कुमार अग्रवाल

सावधान करियर से अधिक जरूरी जीवन है यदि जीवन ही नष्ट कर लिया तो करियर का क्या करोगे? यह सवाल पिछले एक लम्बे समय से हर उस हादसे के बाद सामने आता है जिसमें एक ऊर्जावान युवा जीवन तिरोहित हो चुका होता है सिर्फ परिवार की महत्वाकांक्षाओं के चलते किशोर अवस्था से युवा वय में कदम रखते बच्चों के दिल दिमाग में इतना तनाव और दबाव जाने अनजाने में अभिभावक टीचर भर देते हैं कि कुछ बच्चे बीच रास्ते में इस सीमा तक टूट जाते हैं कि जीवन खत्म कर लेते हैं जबकि लाखों बच्चे मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं।

हाल ही में रुड़की आईआईटी के एक युवा छात्र की असमय मृत्यु की खबर मन को झकझोर देने वाली है। यह घटना सभी अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के लिए आत्ममंथन का विषय है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रुड़की स्थित भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान (आईआईटी) के 19 वर्षीय एक छात्र ने अपने छात्रावास के कमरे में कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी । रुड़की की पुलिस क्षेत्राधिकारी ओशीन जोशी ने बताया कि घटना की सूचना देर रात करीब एक बजे मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची।उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले आयुष राजौरिया (19) के रूप में हुई है जो द्वितीय वर्ष का छात्र था। जोशी ने बताया कि मौके से कथित आत्महत्या से पूर्व लिखा एक नोट बरामद हुआ है जिसमें उसने माता-पिता, दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों या पढ़ाई किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है।उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है । प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें छात्र ने जिंदगी से परेशान होने और जीवन का आनंद नहीं उठा पाने की बात लिखी है. पुलिस के मुताबिक आयुष राजोरिया गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन का रहने वाला था. वह आईआईटी रुड़की में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था और सेकंड ईयर का छात्र था.बताया गया कि वह संस्थान परिसर में रहकर पढ़ाई कर रहा था. शुक्रवार को उसका शव आईआईटी रुड़की के ही हॉस्टल में मिला है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में कमरे से सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई है. सुसाइड नोट में आयुष ने जिंदगी से परेशान होने और जीवन का आनंद नहीं उठा पाने का जिक्र किया है. पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. छात्र ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. हालांकि पुलिस अभी आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह की जांच कर रही है. पुलिस ने छात्र के मोबाइल फोन और अन्य सामान की भी जांच शुरू कर दी है. वही घटना के बाद आईआईटी रुड़की परिसर में छात्र-छात्राओं और शिक्षकों के बीच शोक का माहौल है. पुलिस छात्र के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से भी जानकारी जुटा रही है.

पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधनः सत्ता परिवर्तन की नई आहट

ललित गर्ग

पंजाब की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का छह वर्ष बाद फिर साथ आना केवल दो राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की वापसी नहीं है, बल्कि यह पंजाब के बदलते राजनीतिक समीकरणों की महत्वपूर्ण आहट है, इससे आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ेगा और पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। गुरुनानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर घोषित यह गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार के सामने एक मजबूत चुनौती के रूप में उभर सकता है। दोनों दलों का पुराना राजनीतिक रिश्ता, साझा शासन का अनुभव और एक-दूसरे के पूरक सामाजिक आधार इस गठबंधन को विशेष महत्व देते हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में किसी गठबंधन की घोषणा सत्ता परिवर्तन की गारंटी नहीं होती, लेकिन इतना निश्चित है कि पंजाब में अब मुकाबला पहले की तुलना में अधिक रोचक, प्रतिस्पर्धी और त्रिकोणीय हो गया है। भाजपा और अकाली दल का संबंध राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के औपचारिक गठन से भी पुराना है। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और प्रकाश सिंह बादल के दौर में दोनों दलों ने जिस राजनीतिक साझेदारी की नींव रखी थी, वह लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में सफल मॉडल बनी रही। अकाली दल का ग्रामीण और सिख समाज में प्रभाव तथा भाजपा का शहरी हिंदू, व्यापारी और मध्यवर्गीय आधार एक-दूसरे के पूरक रहे। इसी सामाजिक और राजनीतिक समीकरण के कारण दोनों दलों ने मिलकर पंजाब में कई बार सत्ता हासिल की। लेकिन 2020 में तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के व्यापक आंदोलन के बीच यह रिश्ता टूट गया। अकाली दल ने भाजपा से दूरी बनाई और हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उस समय यह निर्णय किसानों की भावनाओं और पंजाब की राजनीतिक परिस्थितियों के दबाव में लिया गया था, लेकिन बाद के चुनावों ने यह भी दिखाया कि इस अलगाव की राजनीतिक कीमत दोनों दलों को चुकानी पड़ी।

2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीतकर पंजाब की सत्ता पर शानदार ढंग से कब्जा किया। दूसरी ओर अकाली दल तीन और भाजपा केवल दो सीटों तक सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दल अलग-अलग मैदान में उतरे। कांग्रेस ने सात, आम आदमी पार्टी ने तीन और अकाली दल ने एक सीट जीती, जबकि भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालांकि भाजपा का मत प्रतिशत करीब 18.6 प्रतिशत रहा और अकाली दल को भी लगभग 13.5 प्रतिशत वोट मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों दलों के पास अलग-अलग पर्याप्त राजनीतिक आधार है, लेकिन अलग-अलग लड़ने पर वह वोट प्रभावी सीटों में परिवर्तित नहीं हो पा रहा है। अब छह वर्ष बाद दोनों दलों ने अपने अनुभवों से सबक लेते हुए फिर साथ आने का फैसला किया है। इसे राजनीतिक भूल-सुधार भी कहा जा सकता है और बदली परिस्थितियों की व्यावहारिक स्वीकृति भी। इस गठबंधन का सबसे बड़ा प्रभाव आम आदमी पार्टी पर पड़ना स्वाभाविक है। 2022 में आप को सबसे बड़ा लाभ विपक्ष के बिखरे होने से मिला था। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा अलग-अलग चुनाव लड़ रहे थे और सत्ता विरोधी मत एकजुट विकल्प में परिवर्तित नहीं हो पाए। अब भाजपा और अकाली दल के साथ आने से यह समीकरण बदल गया है। भाजपा का शहरी और मध्यवर्गीय आधार तथा अकाली दल का ग्रामीण संगठन और पारंपरिक जनसंपर्क यदि प्रभावी ढंग से एक-दूसरे के पक्ष में वोट ट्रांसफर कर पाते हैं, तो आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से चुनौती बढ़ेगी। यही कारण है कि इस गठबंधन को पंजाब की वर्तमान सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक खतरे की शुरुआत माना जा सकता है।

भाजपा के लिए भी यह गठबंधन रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पंजाब में उसने अपना मत प्रतिशत बढ़ाया है, लेकिन उसे सीटों में बदलने में कठिनाई रही है। अकेले चुनाव लड़कर व्यापक ग्रामीण और सिख सामाजिक आधार तक पहुंच बनाना उसके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। अकाली दल के साथ आने से उसे पंजाब की स्थानीय सामाजिक संरचना में अधिक व्यापक पहुंच मिल सकती है। दूसरी ओर अकाली दल के लिए यह गठबंधन राजनीतिक पुनर्जीवन का अवसर है। कभी पंजाब की राजनीति की निर्णायक शक्ति रहे अकाली दल का जनाधार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से कमजोर हुआ है। भाजपा के साथ लौटना उसके लिए केवल सत्ता में वापसी की कोशिश नहीं, बल्कि संगठन और कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा करने का अवसर भी है। फिर भी इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती विश्वसनीयता की है। छह वर्ष पहले जिस कृषि कानून मुद्दे पर दोनों दल अलग हुए थे, अब उसी रिश्ते को पुनर्जीवित करने पर स्वाभाविक सवाल उठेंगे। अकाली दल को अपने मतदाताओं को समझाना होगा कि परिस्थितियां क्यों बदलीं और आज भाजपा के साथ आने का आधार क्या है। भाजपा को भी किसानों के साथ संवाद की नई और भरोसेमंद भाषा विकसित करनी होगी। लोकतंत्र में गठबंधन बनाना राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन जनता के विश्वास का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी भी है। विचारधारात्मक मतभेदों के बावजूद साथ आना अपने आप में अवसरवाद नहीं है, समस्या तब होती है जब राजनीतिक दल अपने पुराने रुख और वर्तमान निर्णय के बीच कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राजनीतिक अनुभवों की पृष्ठभूमि में पंजाब का घटनाक्रम भाजपा की रणनीति को समझने का एक अवसर देता है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने लंबे समय से मजबूत राजनीतिक आधार रखने वाली शक्तियों के बीच अपनी जगह बनाई और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मजबूत सत्ता को चुनौती देकर सत्ता हासिल की। पंजाब में परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन भाजपा अब यहां भी संगठन, गठबंधन और सामाजिक समीकरणों के माध्यम से सत्ता की संभावना तलाश रही है। अकाली दल का साथ इस रणनीति को स्थानीय आधार दे सकता है। लेकिन पंजाब की जनता केवल राजनीतिक गणित से प्रभावित नहीं होगी। किसान, युवा, रोजगार, नशा, उद्योग, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और राज्य की आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे चुनाव का वास्तविक आधार बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा-अकाली गठबंधन को कागज पर वोट जोड़ने से आगे बढ़कर जमीन पर कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को जोड़ना होगा। छह वर्ष तक अलग रहने के बाद दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच पैदा हुई दूरी को समाप्त करना आसान नहीं होगा। नेतृत्व का समझौता हो जाना पर्याप्त नहीं है, बूथ स्तर तक राजनीतिक सहयोग और आपसी विश्वास जरूरी होगा। यदि भाजपा कार्यकर्ता अकाली उम्मीदवार के लिए और अकाली कार्यकर्ता भाजपा उम्मीदवार के लिए पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तभी गठबंधन की वास्तविक शक्ति सामने आएगी। पंजाब में अब चुनावी मुकाबला केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं रह गया है। यह आम आदमी पार्टी के शासन के मूल्यांकन, कांग्रेस की वापसी की कोशिश और भाजपा-अकाली गठबंधन की नई राजनीतिक संभावनाओं के बीच त्रिकोणात्मक मुकाबला होगा। भाजपा-अकाली गठबंधन निश्चित रूप से आप के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन इसे सत्ता परिवर्तन की गारंटी मानना भी उचित नहीं होगा। अंततः चुनावी निर्णय जनता के प्रदर्शन और विश्वास पर निर्भर करेगा। यदि आप सरकार जनता के बीच अपना भरोसा बनाए रखती है तो गठबंधन की चुनौती सीमित रह सकती है, लेकिन यदि सत्ता विरोधी भावना मजबूत हुई तो भाजपा-अकाली गठबंधन उस भावना को एक संगठित राजनीतिक विकल्प दे सकता है। इस गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि क्या भाजपा और अकाली दल केवल सत्ता पाने के लिए फिर साथ आए हैं या पंजाब के लिए कोई साझा भविष्य-दृष्टि भी रखते हैं। यदि वे किसानों के सम्मान, युवाओं के रोजगार, नशामुक्त पंजाब, उद्योग के विकास, कानून-व्यवस्था और हिंदू-सिख भाईचारे को अपने साझा एजेंडे का केंद्र बनाते हैं तो यह गठबंधन केवल चुनावी समझौता नहीं, पंजाब की राजनीति में नई धुरी बन सकता है। 2020 का अलगाव, 2022 की हार और 2024 का अलग-अलग चुनाव दोनों दलों को यह सिखा चुका है कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन साझा राजनीतिक जमीन को पूरी तरह खो देना किसी के हित में नहीं।

अब 2027 बताएगा कि यह पुनर्मिलन केवल सत्ता की मजबूरी है या वास्तव में पंजाब की राजनीति में एक नई शुरुआत एवं शुभ भविष्य की आहट है।

ट्रंप ने अमेरिका में फेडरल रिजर्व को घेरा!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

भारत की 7 प्रतिशत विकास दर क़ा उदाहरण देकर भारत का बजाया डंका!

7 प्रतिशत विकास दर से दुनियाँ हैरान,?1.86 करोड़ की बरामदगी से खुला भ्रष्टाचार का खेल क्या 31 दिसंबर 2027 तक भारत हासिल करेगा मिशन जीरो भ्रष्टाचार?चिप से शिप तक रोजगार,सेमीकंडक्टर, वैश्विक व्यापार और नई क्षेत्रीय कूटनीति आत्मनिर्भरता और सोने की शुद्धता पर सवाल और बजट 2027 -28 में आर्थिक क्रांति की तैयारी? -समग्र व्यापक महा-विश्लेषण

एक तरफ ?76.50 करोड़ की टैक्स चोरी,दूसरी तरफ भारत की 7प्रतिशत विकास दर की वैश्विक गूंज! सोने में मिलावट, भ्रष्टाचार और चीन की चुनौती के बीच बजट 2027-28 से भारत का निर्णायक आर्थिक प्रहार?

भारत की आर्थिक ताकत से अमेरिका में भी बहस! ट्रंप ने फेडरल रिजर्व को घेरा,भारत की 7 प्रतिशत विकास दर को बनाया मिसाल,अब भ्रष्टाचार मुक्त शासन,रोजगार और आत्मनिर्भरता का अगला इम्तिहान!सोने की शुद्धता पर संकट,सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार और चीन की आर्थिक चुनौती! क़्या बज़ट 2027-28 भारत को बनाएगा अगली वैश्विक आर्थिक महाशक्ति?

वैश्विक स्तरपर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक मोड़ 21 नवंबर 2026 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं का संकेत दे रहा है।एक तरफ केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं,दूसरी तरफ सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार, जीएसटी चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले आर्थिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की लगभग 7 प्रतिशत आर्थिक विकास दर का उदाहरण देकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीति की आलोचना करना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति को चर्चा के केंद्र में ले आया है। सोने की कीमतों में गिरावट,सोने की शुद्धता जांचने की तकनीक पर उठते सवाल,भारत - यूरोपीय संघ व्यापार संबंध, सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता और चीन के मुकाबले क्षेत्रीय सहयोग की रणनीति भी इसी बदलते आर्थिक परिदृश्य के महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह बताना चाहूंगा कि सवाल केवल यह नहीं है कि भारत कितनी तेजी से विकास करेगा,बल्कि यह भी है कि विकास का लाभ आम नागरिक,युवा,किसान,उद्यमी और रोजगार तलाश रहे लोगों तक कितनी पारदर्शिता से पहुंचेगा।

साथियों बात अगर हम ट्रंप का भारत की विकास दर का उदाहरणः वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की चर्चा को समझने की करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 नवंबर 2026 को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति पर तीखी आलोचना की। उन्होंने केंद्रीय बैंक को राजनीतिक बताते हुए आरोप लगाया कि अच्छे आर्थिक आंकड़े आने के बाद भी ब्याज दरें बढ़ाकर अमेरिकी विकास की गति प्रभावित की जाती है।ट्रंप ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों के साथ लगभग 7 प्रतिशत आर्थिक विकास हो रहा है और यदि अमेरिका में भी ब्याज दरें कम रखी जाएं तो उसकी अर्थव्यवस्था 14,15 अथवा 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।उन्होंने यह भी दावा किया कि कम ब्याज दरों से अमेरिका तेजी से विकास कर अपना राष्ट्रीय कर्ज चुकाने में सक्षम होगा।यह बयान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही। अक्टूबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने रेपो दर 5.50 प्रतिशत निर्धारित की थी।लेकिन यहां एक आर्थिक अंतर समझना जरूरी है। ब्याज दरें घटाने से कर्ज सस्ता हो सकता है, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन मिल सकता है, परंतु इससे अपने आप 15 से 20 प्रतिशत विकास दर हासिल नहीं होती। केंद्रीय बैंकों को महंगाई, मुद्रा स्थिरता, रोजगार, ऋण और वित्तीय जोखिमों का संतुलन बनाना पड़ता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता भी इसी संस्थागत व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। अतः ट्रंप का 20 प्रतिशत विकास वाला दावा राजनीतिक एवं आर्थिक अनुमान है, कोई प्रमाणित पूर्वानुमान नहीं।भारत के लिए वास्तविक उपलब्धि यह होगी कि वह महंगाई नियंत्रित रखते हुए निवेश, उत्पादन, निर्यात और रोजगार में निरंतर वृद्धि हासिल करे।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार और कर चोरीः आर्थिक विकास की जड़ों पर दोहरे प्रहार को समझने की करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में सरकारी भ्रष्टाचार और कर चोरी शामिल हैं। हरियाणा के पंचकूला में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग में तैनात अधीक्षक लवकुश कुमार को 19 नवंबर 2026 को कथित रूप से 10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ा।

इसके बाद 20 नवंबर को उनके आवास पर तलाशी के दौरान लगभग 24.29 लाख रुपये भारतीय मुद्रा, 15.65 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा तथा लगभग 1.46 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और चांदी सहित कुल 1.86 करोड़ रुपये की संपत्ति बरामद होने की जानकारी सामने आई। छह बैंक खातों, निवेश पोर्टफोलियो,बीमा और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं।इन संपत्तियों के स्रोत की जांच जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलेगा।इसी बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच 45 फर्मों की जांच में 76.50 करोड़ रुपये की कथित जीएसटी चोरी सामने आई। इनमें से 27.94 करोड़ रुपये सरकारी राजकोष में जमा कराए गए। बोगस फर्मों से खरीद दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ लेना,बिना कर भुगतान बिक्री करना और स्टॉक में अनियमितताएं प्रमुख गड़बड़ियों में शामिल थीं।ये दोनों घटनाएं अलग-अलग प्रकृति की हैं, लेकिन इनसे एक बड़ी आर्थिक समस्या उजागर होती है। रिश्वतखोरी सरकारी निर्णयों की निष्पक्षता को कमजोर करती है,जबकि कर चोरी सरकार की विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध राजस्व को प्रभावित करती है। यदि करदाता ईमानदारी से कर जमा करे और सरकारी व्यवस्था में ही भ्रष्टाचार पनपता रहे, तो आर्थिक न्याय का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

दल-बदल कानून में सुधार की जरूरतः लोकतंत्र के जनादेश की पवित्रता का सवाल

सौरभ वार्ष्णेय

भारत का संसदीय लोकतंत्र केवल चुनाव कराने और सरकारें बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी वास्तविक शक्ति जनता द्वारा दिए गए जनादेश के सम्मान, निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही और संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता में निहित है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में जिस तरह दल-बदल, विधायकों व सांसद के सामूहिक इस्तीफे और सरकारों के बहुमत को प्रभावित करने की घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत लागू दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादी राजनीति पर अंकुश लगाना था, लेकिन समय के साथ इस कानून की सीमाएं भी उजागर हुई हैं। ऐसे में दल-बदल कानून में व्यापक सुधार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार और चुनाव आयोग सहित संबंधित संस्थाओं को नोटिस जारी करना एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।

यह मुद्दा इसलिए चर्चा में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका ने एक ऐसी संवैधानिक खामी की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक परिस्थितियों में सरकारों के बहुमत को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ सांसद और विधायक दल-बदल के मामलों में अयोग्यता की कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफे का रास्ता अपनाते हैं। यदि किसी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है और वह फैसला आने से पहले इस्तीफा दे देता है, तो दल-बदल कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विशेष रूप से तब, जब ऐसे इस्तीफों के परिणामस्वरूप सदन की संख्या और सरकार के बहुमत का गणित बदल जाता है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से बचने के लिए इस्तीफे को कानूनी ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है? लोकतंत्र में इस्तीफा देना किसी जनप्रतिनिधि का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल यदि संवैधानिक जवाबदेही से बचने या जनादेश को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, तो उसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक हो जाती है। इस्तीफा व्यक्तिगत राजनीतिक निर्णय हो सकता है, लेकिन उसके पीछे की परिस्थितियों और समय का संवैधानिक महत्व भी है।

वर्ष 1985 में संविधान के 52वें संशोधन के माध्यम से दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की राजनीतिक निष्ठा में अवसरवादी बदलाव को रोकना और सरकारों को अनावश्यक अस्थिरता से बचाना था। बाद में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से दल-बदल संबंधी प्रावधानों को और कठोर बनाया गया तथा मंत्रिपरिषद के आकार पर भी सीमा निर्धारित की गई। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के बीच सत्ता हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में नए-नए रास्ते तलाशे जाते रहे हैं। कभी सामूहिक इस्तीफे, कभी सदन से अनुपस्थिति और कभी अयोग्यता की कार्यवाही को लंबा खींचने जैसे मामलों ने इस कानून की व्यावहारिक प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं।

इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी यह मानी जाती है कि अयोग्यता संबंधी मामलों पर प्रारंभिक निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर या सभापति के पास होता है। संवैधानिक रूप से यह व्यवस्था संसदीय संस्थाओं की स्वायत्तता और गरिमा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। लेकिन जब स्पीकर स्वयं किसी राजनीतिक दल से निर्वाचित होकर आते हैं, तब राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगते हैं। कई बार अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय में लंबी देरी होती है। परिणामस्वरूप संबंधित सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग लेते रहते हैं और इस दौरान राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं।

यह स्वीकार करना होगा कि स्पीकर का पद केवल सदन की कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे संवैधानिक निष्पक्षता और संस्थागत मर्यादा की अपेक्षा भी की जाती है। इसलिए दल-बदल से जुड़े मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी निर्णय व्यवस्था लोकतंत्र की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट पहले भी स्पीकर के निर्णयों में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त कर चुका है। अब नई जनहित याचिका के माध्यम से इस्तीफे और अयोग्यता की कार्यवाही के बीच संबंध को स्पष्ट करने की मांग उठी है।

याचिका में यह भी महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया है कि यदि किसी सांसद या विधायक के विरुद्ध दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही लंबित है अथवा उसके शुरू होने की उचित आशंका है, तो उसका इस्तीफा अपने आप उस कार्यवाही को समाप्त नहीं कर देना चाहिए। इस्तीफे की स्वेच्छा और वास्तविकता की जांच वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। साथ ही लंबित अयोग्यता याचिका पर स्वतंत्र रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। यह मांग इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इस्तीफे के माध्यम से अयोग्यता की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बनाया जा सकता है, तो दल-बदल विरोधी कानून का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाएगा। हालांकि इस विषय पर किसी भी सुधार के दौरान एक अन्य संवैधानिक पक्ष को भी ध्यान में रखना होगा। जनप्रतिनिधि को अपने पद से इस्तीफा देने का अधिकार संविधान और संसदीय व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए हर इस्तीफे को राजनीतिक साजिश या दल-बदल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कई बार जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत, नैतिक या राजनीतिक कारणों से भी इस्तीफा देते हैं। ऐसे में सुधार का उद्देश्य इस्तीफे के अधिकार को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग की संभावनाओं को रोकना होना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट कानूनी मानदंड, निष्पक्ष जांच और न्यायसंगत प्रक्रिया जरूरी है।

त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में सरकार गठन और बहुमत परीक्षण का मुद्दा भी इस जनहित याचिका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। याचिका में कहा गया है कि बहुमत का परीक्षण विधिवत गठित सदन के पटल पर होना चाह



बाल दिवस

नेहरू जी का बाल प्रेम



चाचा जी ने सोचा शायद वह बगीचे में ही कहीं माली के साथ काम कर रही होगी। नेहरू जी यह सोच ही रहे थे कि बच्चे ने रोना तेज कर दिया। इस पर उन्होंने उस बच्चे की मां की भूमिका निभाने का मन बना लिया। नेहरू जी ने बच्चे को उठाकर अपनी बांहों में लेकर उसे थपकियां दीं, तो बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बच्चे को मुस्कुराते देख चाचा जी खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की मां दौड़ते वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका बच्चा नेहरू जी की गोद में मंद-मंद मुस्कुरा रहा था।

जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे और तीन मूर्ति भवन उनका सरकारी निवास था। एक दिन तीन मूर्ति भवन के बगीचे में लगे पेड़-पौधों के बीच से गुजरते हुए घुमावदार रास्ते पर नेहरू जी टहल रहे थे और पौधों पर छाई बहार देखकर खुशी से निहाल हो ही रहे थे, तभी उन्हें एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। नेहरू जी ने आसपास देखा तो उन्हें पेड़ों के बीच एक-दो माह का बच्चा दिखाई दिया, जो दहाड़ मारकर रो रहा था। नेहरू जी ने मन ही मन सोचा- इसकी मां कहां होगी? उन्होंने इधर-उधर देखा। वह कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। चाचा जी ने सोचा शायद वह बगीचे में ही कहीं माली के साथ काम कर रही होगी। नेहरूजी यह सोच ही रहे थे कि बच्चे ने रोना तेज कर दिया। इस पर उन्होंने उस बच्चे की मां की भूमिका निभाने का मन बना लिया। नेहरू जी ने बच्चे को उठाकर अपनी बांहों में लेकर उसे थपकियां दीं, तो बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बच्चे को मुस्कुराते देख चाचा जी खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की मां दौड़ते वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका बच्चा नेहरू जी की गोद में मंद-मंद मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही एक बार जब पंडित नेहरू जी तमिलनाडु के दौरे पर गए, तब जिस सड़क से वे गुजर रहे थे वहां वे लोग साइकिलों पर खड़े होकर तो कहीं दीवारों पर चढ़कर नेताजी को निहार रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहां समझ आया वहां खड़े होकर नेहरू को निहारने लगा। इस भीड़भरे इलाके में नेहरू जी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के तरह-तरह के रंग-बिरंगी गुब्बारे मानो पंडितजी को देखने के लिए डोल रहे हो। नेहरू जी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुंची तो गाड़ी से उतर कर वे गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े तो गुब्बारे वाला हक्का-बक्का सा रह गया। नेहरू जी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाएं और वहां उपस्थित सारे बच्चों को वे गुब्बारे बंटवा दिए। ऐसे प्यारे चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। नेहरूजी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे-जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुंचे, बच्चों ने चाचा नेहरू-चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहां का वातावरण उल्लासित कर दिया। तभी से वे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हो गए।

प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं

14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है। इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू पुकारते थे। बाल दिवस बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। देश की आजादी में भी नेहरू का बड़ा योगदान था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश का उचित मार्गदर्शन किया था। बाल दिवस बच्चों के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन स्कूली बच्चे बहुत खुश दिखाई देते हैं। वे सज-धज कर विद्यालय जाते हैं। विद्यालयों में बच्चे विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वे अपने चाचा नेहरू को प्रेम से स्मरण करते हैं। बाल मेले में बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसमें बच्चे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। नृत्य, गान, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा आम लोगों को शिक्षा का महत्व बताया जाता है। बच्चे देश का भविष्य हैं। इसलिए हमें सभी बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। बच्चों के रहन-सहन के स्तर ऊंचा उठाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इन्हें स्वस्थ, निर्भीक और योग्य नागरिक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह बाल दिवस का संदेश है। बाल दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा करती है। बाल श्रम रोधी कानूनों को सही मायनों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। अनेक कानून बने होने के बावजूद बाल श्रमिकों की संख्या में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती जा रही है। इन बच्चों का सही स्थान कल-कारखानों में नहीं बल्कि स्कूल है।



अन्य देशों में बाल दिवस

भारत में यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। कहा जाता है कि पंडित नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे, इसलिए बाल दिवस मनाने के लिए उनका जन्मदिन चुना गया। दरअसल, बाल दिवस की नींव 1925 में रखी गई थी, जब बच्चों के कल्याण पर विश्व कान्फ्रेंस में बाल दिवस मनाने की सर्वप्रथम घोषणा हुई। 1954 में दुनिया भर में इसे मान्यता मिली। संयुक्त राष्ट्र ने यह दिन 20 नवंबर के लिए तय किया, लेकिन अलग-अलग देशों में यह अलग दिन मनाया जाता है। कुछ देश 20 नवंबर को भी बाल दिवस मनाते हैं। 1950 से बाल संरक्षण दिवस यानी 1 जून भी कई देशों में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि हर बच्चा खास है और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए उनकी मूल जरूरतों और पढ़ाई लिखाई की जरूरतों का पूरा होना बेहद जरूरी है। यह दिन बच्चों को उचित जीवन दिए जाने की भी याद दिलाता है।

संविधान में बाल अधिकार

भारत का संविधान, संयुक्त राष्ट्र की योजनाओं के ही अनुरूप बच्चों के संरक्षण एवं अधिकारों की रक्षा के लिए कई सुविधाएं देता है। संविधान हर तरह से देश में बच्चों के कल्याण और उनकी शिक्षा एवं बालश्रम से मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

- अनुच्छेद 15 (3) : राज्य को बच्चों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 21ए : राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा देना क़ानूनी रूप से बाध्यकारी है।
- अनुच्छेद 24 : बालश्रम को प्रतिबंधित और ग़ैर-क़ानूनी कहा गया है।
- अनुच्छेद 39 (ई) : बच्चों के स्वास्थ्य और रक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए राज्य क़ानूनी रूप से बाध्य है।
- अनुच्छेद 39 (एफ) : बच्चों को गरिमामय रूप से विकास करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की नैतिक ज़िम्मेदारी है।

अमूमन हर अविभावक अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचता है, अच्छे से अच्छा करना चाहता है। और उसे सबसे आगे देखना चाहता है। इतना तक तो ठीक है और बहुत स्वाभाविक भी, लेकिन यहां देखना होगा कि हम बच्चे की प्रतिभा के संपूर्ण विकास की नींव रख रहे हैं या उसे अपनी महत्वाकांक्षा का हिस्सा बनाकर उसकी जिंदगी में अंधेरी दलदल और तनाव परोस रहे हैं।





चाचा नेहरू बच्चों के साथ

नेहरूजी ने बच्चे को उठाकर अपनी बांहों में लेकर उसे थपकियां दीं, झुलाया तो बच्चा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। बच्चे को मुस्कुराते देख चाचा खुश हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। जब बच्चे की मां दौड़ते वहां पहुंची तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका बच्चा नेहरू जी की गोद में मंद-मंद मुस्कुरा रहा था। ऐसे ही एक बार जब पंडित नेहरू तमिलनाडु के दौरे पर गए, तब जिस सड़क से वे गुजर रहे थे, वहां वे लोग साइकिलों पर खड़े होकर तो कहीं दीवारों पर चढ़कर नेताजी को निहार रहे थे। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए हर आदमी इतना उत्सुक था कि जिसे जहां समझ आया, वहां खड़े होकर नेहरू को निहारने लगा। इस भीड़भरे इलाके में नेहरू जी ने देखा कि दूर खड़ा एक गुब्बारे वाला पंजों के बल खड़ा डगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों के तरह-तरह के रंग-बिरंगी गुब्बारे मानो पंडित जी को देखने के लिए डोल रहे हो। जैसे वे कह रहे हों हम तुम्हारा तमिलनाडु में स्वागत करते हैं। नेहरू जी की गाड़ी जब गुब्बारे वाले तक पहुंची तो गाड़ी से उतरकर वे गुब्बारे खरीदने के लिए आगे बढ़े तो गुब्बारे वाला हक्का-बक्का-सा रह गया।

बाल शोषण

आज भी चाचा नेहरू के इस देश में लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जो चाय की दुकानों पर नौकरों के रूप में, फैक्ट्रियों में मजदूरों के रूप में या फिर सड़कों पर भटकते भिखारी के रूप में नजर आ ही जाते हैं। इनमें से कुछेक ही बच्चे ऐसे हैं, जिनका उदाहरण देकर हमारी सरकार सीना ठोककर देश की प्रगति के दावे को सच होता बताती है। यही नहीं, आज देश के लगभग 53.22 प्रतिशत बच्चे शोषण का शिकार हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे अपने रिश्तेदारों या मित्रों के यौन शोषण का शिकार हैं। अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञता एवं अज्ञानता के कारण वे बच्चे शोषण का शिकार होकर जाने-अनजाने कई अपराधों में लिप्त होकर अपने भविष्य को अंधकारमय कर रहे हैं। बचपन आज भी भोला और भावुक ही होता है लेकिन हम उन पर ऐसे-ऐसे तनाव और दबाव का बोझ डाल रहे हैं कि वे कुम्हला रहे हैं। उनकी खनकती-खिलखिलाती किलकारियां बरकरार रहें, इसके ईमानदार प्रयास हमें ही तो करने हैं। देश के ये गुलाबी नवांकुर कोमल बचपन की यादें सहेजें, इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें कठोर और क्रूर नहीं, बल्कि मयूर पंख सा लहलहाता बचपन दें। चाचा नेहरू को दो बातें बहुत पसंद थीं। पहली वे अपनी शेरवानी की जेब में रोज गुलाब का फूल रखते थे और दूसरी वे बच्चों के प्रति बहुत ही मानवीय और प्रेमपूर्ण थे।

समारोह

हर वर्ष बचपन की यादों को ताजा करने के लिए बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिन हमें सिखाता है कि एक निर्दोष और जिज्ञासु बच्चे की तरह हमें सदैव खुश रहना चाहिए और हमेशा सीखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते रहना चाहिए। यह बच्चों के लिए उल्लास में डूब जाने का दिन है। स्कूलों में भी यह दिन बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में इस दिन स्कूलों में प्रश्नोत्तरी, फैंसी परिधान प्रतियोगिता और बच्चों की कला प्रदर्शनियों जैसे कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और कॉर्पोरेट संस्थाओं ने सभी पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए विशेष समारोह और प्रतियोगिताओं का आयोजन शुरू किया है। इस तरह के आयोजन देश के हर कोने में लोकप्रिय हुए हैं। अब टेलीविजन और अन्य मीडिया नेटवर्क समाज के प्रत्येक स्तर पर 14 नवंबर को बच्चों के लिए खास कार्यक्रम बना रहे हैं।

राष्ट्रपति सहभागिता

हर वर्ष राष्ट्रपति भवन में देश भर से आए चुनिंदा बच्चों से भारत के राष्ट्रपति मुलाकात करते हैं। बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और उन्हें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे भी इस मौके पर देश के प्रति अपने विश्वास और भविष्य में चुनौतियों का सामना करने की भावना को व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल का मानना है कि देश के विकास में बच्चों की शिक्षा और अनुशासन का अमूल्य योगदान होता है। उन्होंने देश के शिक्षकों एवं छात्रों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इनकी कड़ी मेहनत तथा संस्कृति ने दुनियाभर में देश का नाम रोशन किया है। देश के 11वें राष्ट्रपति (भूतपूर्व) डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी देश के विकास के लिए बच्चों का विकास आवश्यक मानते हैं। उन्होंने पद पर रहते हुए और बाद में भी कई मौकों पर यह संदेश दिया है कि देश का विकास बच्चों के हाथों में ही है। उन्होंने कहा था कि आज के साथ समझौता करने पर ही हम देश के बच्चों के लिए बेहतर कल दे सकेंगे। बच्चों के साथ उनके सवाल-जवाब पूरे देश में काफी लोकप्रिय हैं।

जारी डाक टिकट

नेहरू जी ने अपने तमिल जानने वाले सचिव से कहकर सारे गुब्बारे खरीदवाए और वहां उपस्थित सारे बच्चों को वे गुब्बारे बंटवा दिए। ऐसे प्यारे चाचा नेहरू को बच्चों के प्रति बहुत लगाव था। नेहरू जी के मन में बच्चों के प्रति विशेष प्रेम और सहानुभूति देखकर लोग उन्हें चाचा नेहरू के नाम से संबोधित करने लगे और जैसे-जैसे गुब्बारे बच्चों के हाथों तक पहुंचे बच्चों ने चाचा नेहरू-चाचा नेहरू की तेज आवाज से वहां का वातावरण उल्लासित कर दिया।

अमेरिकी एजेंसियों को जासूसी ऑपरेशन के सबूत नहीं मिले

एनवीडिया सीईओ हुआंग-एलिस हुआंग अफेयर

वाशिंगटन। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के कथित अफेयर को लेकर दुनिया में मची सनसनी अब शांत होती दिख रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की शुरुआती जांच में इस मामले को चीन की ओर से चलाए गए जासूसी ऑपरेशन के तौर पर साबित करने वाले कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पहले दावा किया गया था कि चीन की एलिस हुआंग ने जेनसन हुआंग को रिश्ते में फंसाकर संवेदनशील जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी, जिसके चलते जेनसन को सीईओ पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था, हालांकि बाद में उन्हें उनकी कुर्सी वापस मिल गई। अब, सीआईए, एफबीआई और एनएसए समेत अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस कथित साजिश का कोई ठोस प्रमाण नहीं पाया है। अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के बीच रिश्ता निजी हो सकता है, न कि चीन की ओर से चलाया गया कोई जासूसी ऑपरेशन। एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, सीआईए, एफबीआई, एनएसए और ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने कांग्रेस के कर्मचारियों को एक गोपनीय ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब तक मिले सबूतों से यह साबित नहीं होता कि चीन की सरकार ने एलिस हुआंग को जेनसन हुआंग के करीब जाने का निर्देश दिया था। हालांकि, इस मामले में एलिस हुआंग को पूरी तरह क्लीन चिट नहीं मिली है। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनका चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (एमएसएस) से संपर्क रहा था। इस एजेंसी ने उनसे जानकारी हासिल करने के लिए संपर्क किया था। लेकिन जांच में अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि एलिस ने चीन की एजेंसी को कोई अहम खुफिया जानकारी दी हो, या यह रिश्ता जासूसी के लिए रचा गया ऑपरेशन था।

इस मामले में कांग वेई नाम के एक व्यक्ति का जिक्र भी अहम है, जिन्हें अक्सर एलिस हुआंग के पति के रूप में पेश किया जाता था। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने उन्हें एलिस के मुकाबले चीन की खुफिया एजेंसी से ज्यादा मजबूत संबंध रखने वाला व्यक्ति बताया है। कांग वेई के एमएसएस के साथ करीबी संपर्क होने की बात सामने आई है, जिससे जांच का दायरा सिर्फ एलिस और जेनसन के रिश्ते तक सीमित नहीं रह गया है।

जानकारों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारियों ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि अफेयर शुरू होने के बाद एलिस हुआंग ने चीन को कुछ खुफिया जानकारी दी हो। कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग में कुछ बेहद संवेदनशील खुफिया जानकारियां शामिल नहीं थीं, और एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की निगरानी में तैयार गोपनीय मेमो का भी जिक्र किया गया था, जिसमें जेनसन हुआंग और एलिस के रिश्ते के साथ-साथ एलिस के कथित खुफिया संपर्कों का विवरण था।

सपा के मैनिफेस्टो : 5000 रुपये भत्ता, 5 में खाना, 300 यूनिट मुफ्त बिजली

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस घोषणा पत्र में जेनजी का खास ख्याल रखा गया है. 5 हजार रुपये मासिक भत्ते से लेकर नौकरियों तक के वादे किए गए हैं.



उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने पर अगले पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. इसके अलावा 2 से 3 करोड़ युवाओं को दूसरे क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. सरकारी विभागों में सभी खाली पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे और भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा. पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ सभी परीक्षाएं समय पर कराने का वादा किया गया है.

सपा ने हर साल 5 लाख युवाओं को कौशल विकास केंद्रों के जरिए प्रशिक्षित करने और एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से 2032 तक एक करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है. पार्टी ने वादा किया है कि नौकरी मिलने तक बेरोजगार युवाओं को हर महीने 5 हजार रुपये पोषण भत्ता दिया जाएगा. एआई से प्रभावित होने वाले युवाओं को नई तकनीक का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा. अग्निवीर योजना के विरोध में राज्य पुलिस और अन्य विभागों में युवाओं को रोजगार देने का भी ऐलान किया गया है. इसके अलावा छात्राओं के लिए तहसील स्तर पर कौशल विकास और करियर परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएंगे.

समाजवादी पार्टी ने सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने और पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक (PDA) वर्ग के सामाजिक व आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया है. पार्टी ने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है. निजी स्कूलों में आरक्षित वर्ग के छात्रों की फीस सरकार जमा करेगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए बजट का 20 फीसदी खर्च करने का भी वादा किया गया है.

सपा ने PDA, महिलाओं और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन खोलने का ऐलान किया है, जहां 5 रुपये में थाली मिलेगी. प्रवासी मजदूरों के लिए हेल्पलाइन बनाई जाएगी और बुजुर्ग महिला कारीगरों को सालाना 40 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम लाने के साथ वृद्धाश्रम और क्लब बनाए जाएंगे. दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल के साथ सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया है.

सरकारी ठेकों और लाभार्थी योजनाओं में गरीब एवं शोषित वर्गों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है. अनुसूचित जनजाति और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अलग-अलग बोर्ड बनाए जाएंगे.

बेटी से मिलने आए रिटायर्ड फौजी की पीट-पीटकर हत्या, समधी, दामाद

झुंझुनूं. राजस्थान के झुंझुनूं के सूरजगढ़ से बड़ी खबर है. बेटी से मिलने आए एक रिटायर्ड फौजी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. मामले में सूरजगढ़ पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मृतक का समधी, दामाद और बेटी का देवर शामिल है.

मृतक सुरेश कुमार हरियाणा के रहने वाले थे. वे अपनी बेटी का हाल-चाल जानने चिड़ावा आए थे. इसी दौरान वे बेटी के ससुराल पहुंचे और उसके ससुर, पति व देवर से बातचीत करने लगे.

बताया जा रहा है कि मकान पर पहुंचते ही तीनों ने सुरेश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मारपीट में गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई. यह वारदात



कुछ दिन पहले चिड़ावा कस्बे के सूरजगढ़ बाईपास पर हुई थी. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, सुरेश कुमार रविवार को अपनी बेटी मोनू से मिलने आए थे. आरोप है कि बेटी के ससुराल पक्ष से बातचीत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई. गंभीर चोटों के चलते इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मोनू की शादी साल 2012 में मनोहरपुरा निवासी होशियार सिंह से हुई थी.

सुरेश कुमार के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही मोनू को दहेज और घरेलू विवादों को लेकर परेशान किया जा रहा था. परिवार ने कई बार बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश भी की थी.

यूपी में 'अब्दुल' डिप्टी सीएम बनेगा, रैली में बोले चंद्रशेखर आजाद- दरी नहीं बिछाएगा, मेरे बराबर में बैठेगा

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी पारा अब बढ़ने लगा है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में अपने गठबंधन सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' की। इस रैली में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में 'अब्दुल' डिप्टी सीएम बनेगा।

दरअसल ओवैसी ने गठबंधन का ऐलान करते वक्त ही यह साफ कर दिया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा चंद्रशेखर आजादी ही होंगे। इसी एक बात और जोड़ते हुए आजाद ने कहा, 'यूपी में अब्दुल डिप्टी सीएम बनेगा। अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि मेरे बराबर में बैठेगा।



हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि एक डिप्टी दूसरे वर्ग से भी एक डिप्टी सीएम बनाएंगे।

इसके अलावा आसपा अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यह भी ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद उनकी पार्टी महिलाओं को 25 हजार रुपए महीना देगी। उन्होंने कहा कि न्याय बुलडोजर से नहीं, बल्कि संविधान से होगा।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन पर और चंद्रशेखर आजाद पर गोलियां चलाई गई, लेकिन वे ऐसे अत्याचार के सामने चुप रहने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि वे बदलाव लाने के लिए आगे आए हैं। ओवैसी ने कहा, 'अगर उत्तर प्रदेश में गरीबों, शोषितों और पिछड़े लोगों की सरकार बननी है, जो किसी एक जाति की नहीं बल्कि जनता की सरकार हो, तो उसका मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद होगा।

उन्होंने आगे कहा कि देश और उत्तर प्रदेश में जहर और नफरत बढ़ने के लिए दो लोग जिम्मेदार हैं- नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ।

लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की 'बहुजन स्वराज संकल्प महारैली' को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने SIR को संविधान को कमजोर करने का एक और तरीका बताया।

160 करोड़ का 121 किलो सोना तिरुपति को किया दान

चेन्नई। मंदिर में दान-पुण्य करना अच्छा माना जाता है. ऐसे में हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दाम करना है. कोई फल-फूल दान करता है, कोई कपड़े, कोई कैश तो कई लोग सोना चांदी भी दान करते हैं. देश के कई बड़े मंदिरों में लोग किलो- किलो भर सोना और चांदी दान करते हैं. ऐसे में हाल ही में दक्षिण भारत के तिरुपति मंदिर में एक शख्स का सोना दान करना चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल चेन्नई के एक बिजनेसमैन वर्धमान जैन ने साउथ के सुप्रसिद्ध मंदिर तिरुमाला तिरुपति में 121 किलो सोने का दान किया है. जिसकी कीमत 160 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वर्धमान जैन चेन्नई के रहने वाले हैं, जो पेशे से



बिजनेसमैन हैं. वर्धमान ने हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) और ऑटोमेशन के क्षेत्र में काम करते हैं. उन्हें मुख्य रूप से 'एक्सेस हेल्थकेयर' के फाउंडर और फॉर्मर वाइस-चेयरमैन के रूप में जाना जाता है. ये कंपनी हेल्थकेयर इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज देती है. विधर्मान जैन ने पहले चेन्नई के ही लॉयोला कॉलेज से स्टैटिक्स की पढ़ाई की है. जिसके बाद वो स् शिफ्ट हो गए और वहां रहकर उन्होंने ऑस्टिन की टैक्सास यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री की. कुछ साल वहां रहकर जैन ने हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी, मेडिकल कोडिंग, इमेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में एक्सपर्टाइज हासिल की.

बिजनेसमैन के रूप में काम करने से पहले जैन कॉर्पोरेट की दुनिया में भी सीनियर पोजिशंस पर काम किया है. उन्होंने 'विज़न हेल्थसोर्स' की सह-स्थापना भी की और डेल सर्विसेज के BPO डिवीजन में प्रबंध निदेशक के रूप में भी काम किया है. जैन के बिजनेस में साल 2025 में एक बड़ा मोड़ आया, जब उन्होंने कथित तौर पर 'एक्सेस हेल्थकेयर' में अपनी 70% हिस्सेदारी एक अमेरिकी कंपनी को बेच दी.

ये डील लगभग 2 अरब डॉलर में हुई थी. इस ट्रांजैक्शन ने कंपनी को चर्चा में ला दिया और जैन के उद्यमी सफर में एक अहम पड़ाव साबित हुआ.

बाबासाहेब को श्रद्धांजलि देने मेरठ जा रहे सौरव दास का बड़ा दावा, 'मुझे रोक दिया गया और...'

नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने बुधवार को दावा किया कि जब वह संविधान दिवस के मौके पर बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरठ जा रहे थे तो उनको बॉर्डर पर ही रोक लिया गया और आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई. सीजेपी नेता ने सवाल उठाया कि क्या यूपी में बाबासाहेब को फूल चढ़ाना अपराध है?

सौरव दास ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'मैं संविधान दिवस पर बाबासाहेब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरठ जा रहा था, लेकिन मुझे सीमा पर रोक दिया गया और आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। क्या आज उत्तर प्रदेश में बाबासाहेब को फूल चढ़ाना अपराध है? क्या यूपी में बाबासाहेब जी के मूर्ति को माला चढ़ाना आज एक अपराध हे? मैं इसका विरोध



करता हूं.' सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने भी इस पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, 'सौरव को उत्तर प्रदेश में बाबासाहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने से क्यों रोका गया है?'

कॉकरोच जनता पार्टी ने भी सौरव दास को कथित तौर पर रोके जाने को लेकर विरोध जताया. CJP ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिखा, 'यह सरकार बाबासाहेब के संविधान और उनके सिद्धांतों की इतनी विरोधी क्यों है?'

उधर, सीजेपी ने चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार के खिलाफ गुरुवार को नागपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ' प्रदर्शन और जनसभा आयोजित कर रही है.

दीपके ने सरकार पर साधा निशाना

दीपके ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया, 'देशभर में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है. इसकी शुरुआत चुनावों के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त से हुई और फिर हर राज्य में वोटों की चोरी होने लगी. कोल्हापुर में गोकुल डेरी चुनाव हारने के बाद अब वे दूध सहकारी संस्था में अपने लोगों को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावों को हाईजैक कर उनमें धांधली कर रहे हैं.'

संविधान दिवस पर मिला समन तो भड़के वांगचुक, बोले- जरूर पेश होऊंगा लेकिन...

नई दिल्ली। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 26 नवंबर को एक समन जारी किया है. लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) की ओर से जारी इस कारण बताओ नोटिस में वांगचुक को आज दोपहर 3 बजे मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्यों न उनसे शांति बॉन्ड भरवाया जाए. इस पर पलटवार करते हुए सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया.

सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं. इस शुभ दिन पर आज सुबह मुझे ञ प्रशासन की ओर से यह समन



मिला है. मुझे आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर यह समझाने के लिए कहा गया है कि मुझसे शांति बॉन्ड क्यों न भरवाया जाए. इसका सीधा सा कारण ये है कि मैंने हमेशा और केवल शांतिपूर्ण तरीकों जैसे धरना और अनशन की ही अपील की है. यहां तक कि -15 डिग्री की सर्द रातों में भी हमने किसी और को नहीं, बल्कि सिर्फ खुद को ही तकलीफ दिया है.' वांगचुक ने प्रशासन पर उनके बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'यह अलग बात है कि मेरी बातों को अक्सर खींच-तानकर और तोड़-मरोड़कर वैसा मतलब निकाला जाता है, जैसा वे सुनना चाहते हैं. शुक्र है कि इस बार भी मेरे पास पर्याप्त दस्तावेजी सबूत हैं, जैसा कि पिछले साल NSA मामले के दौरान थे. मैं आज निश्चित रूप से पेश होऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा.'

प्रशासन की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 126 और 130 के तहत जारी इस नोटिस का संबंध आगामी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC), लेह के आम चुनाव 2026 से है. 23 नवंबर 2026 को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में दिए गए वांगचुक के भाषण और पुलिस रिपोर्ट का हवाला देते हुए नोटिस में चार मुख्य प्वाइंट्स उठाए गए हैं. पहला- सरकारी कर्मचारियों से चुनाव के दौरान सामूहिक अवकाश पर जाने की अपील करना ताकि चुनावी ड्यूटी के लिए कोई उपलब्ध न रहे.

दूसरा- सर्दियों में चुनाव कराए जाने के विरोध में जनता से प्रदर्शन जारी रखने की अपील करना. तीसरा- यह टिप्पणी करना कि जिन लोगों के पास छिपाने या डरने के लिए कुछ है उन्हें अस्थायी रूप से लद्दाख छोड़ देना चाहिए, और बच्चों से अपने माता-पिता से सवाल करने को कहना. चौथा- मतदान की तारीख को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को लोगों को इकट्ठा होने और 27 नवंबर से 4 दिसंबर तक भूख हड़ताल करने का आह्वान करना. नोटिस में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान इन बयानों से शांति भंग होने की आशंका है.

थलपति विजय सरकार ने तमिलनाडु में पहली बार विवाहित कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की

चेन्नई। तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने राज्य की महिला कर्मचारियों को मिलने वाले मातृत्व अवकाश के जैसा ही राज्य सरकार के विवाहित कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। राज्य में पहली बार सरकारी पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुरुष सरकारी कर्मचारी 15 दिन के पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। वे यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री थलपति विजय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह घोषणा करते हुए बताया कि इस संबंध में



सरकारी आदेश जारी कर दिया गया है। यह अवकाश प्रसव से 15 दिन पहले या बाद में अथवा बच्चे के जन्म की तिथि से छह माह के भीतर लिया जा सकेगा। सीएम विजय ने कहा कि महिला कर्मचारियों को मिलने वाले 365 दिन के मातृत्व अवकाश के अनुरूप पुरुष सरकारी कर्मचारियों के पितृत्व अवकाश की मांग पर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 दिन का अवकाश स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था की अवधि मां और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, और प्रत्याशित मां और बाद में बच्चे की देखभाल में शारीरिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करने में पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कहा कि महिला सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला 365 दिन का मातृत्व अवकाश मातृत्व और बाल कल्याण के महत्व को दर्शाता है। इसी प्रकार, पुरुष कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश प्रदान करने से पारिवारिक जिम्मेदारियों को साझा करने में पिता की भूमिका सुनिश्चित होगी और बच्चे के पालन-पोषण में मदद मिलेगी।

जन्म के समय ही छीन लिया एक अधिकार, नेहा बोरा ने ऐसा आरोप लगा किसे बताया SIR के पीछे की असली चाल

नई दिल्ली। वामपंथी छात्र संगठन AISA (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा मतदाता सूची की SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया का लंबे समय से विरोध करती आ रही हैं और इस प्रक्रिया को भाजपा की वोट चोरी का एक हिस्सा बताती रही हैं। इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक खबर को शेयर किया, और इसके जरिए SIR के पीछे सरकार के असली मकसद को बताने का दावा किया। जिस खबर को उन्होंने शेयर किया, उसमें बताया गया था कि किस तरह पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक ढाई महीने के शिशु को केवल इसलिए जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट) देने से इनकार कर दिया



गया, क्योंकि उसके पिता का नाम SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिया गया था। इसी खबर को अपने 'एक्स' अकाउंट पर शेयर करते हुए नेहा बोरा ने लिखा, 'एक नवजात शिशु को जन्म प्रमाण पत्र देने से इनकार करते हुए जन्म के समय ही उसका एक अधिकार छीन लिया गया।' आगे नेहा ने केंद्र सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मंशा SIR को एक ऐसे हथियार के रूप में उपयोग करने की है जिसके जरिए वो उन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से बाहर कर सकती है, जिनका इस प्रक्रिया से कोई लेना-देना ही नहीं है। नेहा ने इसी को SIR की असली चाल बताया। अपनी पोस्ट में नेहा ने आगे लिखा, 'और बात यहीं खत्म नहीं होती। मोदी-शाह SIR का इस्तेमाल लोगों को बाहर करने की एक ऐसी कड़ी बनाने के लिए कर रहे हैं, जिससे उन्हें कल्याणकारी योजनाओं, अधिकारों और सुविधाओं से वंचित किया जा सके।

कबाड़ सीटें आप ही लें, इन पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे.... कांग्रेस नेता इमरान मसूद की अखिलेश यादव को दो टूक

लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है. शुरुआती दौर में सपा ने कांग्रेस को 26 सीटें देने की पेशकश की है. इस बीच उसने अपने पांच उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी.जिससे वह ये बता सके कि इन सीटों पर तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे. सहारनपुर की दो विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाने ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद काफी नाराज हैं. इसे लेकर ढृढ्ढष्ठढ्ढ ब्लॉक के दोनों सहयोगियों के बीच बड़ा मतभेद की स्थिति बनी हुई है. दरअसल अखिलेश यादव सहारनपुर की दो विधानसभा सीटों पर सपा के उम्मीदवार उतार रहे हैं.इसे लेकर सहारनपुर से लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने अखिलेश पर हमला बोला है.

सहारनपुर देहात और बेहट सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए हुए थी. लेकिन किन अखिलेश ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पूरा गेम ही पलट दिया. अखिलेश के इस दांव से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद नाराज हैं. वह कह रहे हैं, 'हम बेकार (कबाड़) सीटें स्वीकार नहीं करेंगे. अगर आप हमें ऐसी सीटें देगें, जिनको हम नहीं जीत सकते, तो हम उनको नहीं लेंगे.

कांग्रेस सांसद ने अखिलेश से दो टूक कहा कि अगर आपको लगता है कि आप उन सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं तो आप खुद ही उन पर चुनाव लड़ लें. इमरान मसूद ने कहा कि हम उन पर चुनाव क्यों लड़ें? हम केवल उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां हम अच्छे नतीजे दे पाएं.

गुस्साए कांग्रेस सांसद ने कहा कि हम कबाड़ सीट नहीं लेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है. हम वहीं लड़ना है, जहां हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे.उन्होंने अखिलेश से दो टूक कह दिया कि अपने संगठन को, अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता. उन्होंने साफ किया कि हमारी जीतने की क्षमता को तय करने का अधिकार आपका नहीं बल्कि हमारी अपनी पार्टी का है.

दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर उत्पादकों ने किया धरना प्रदर्शन



के.के.पी संवाददाता

भिकियासैण (अल्मोड़ा)। दुग्ध अवशीतन केंद्र जेठुआ में उत्पादक व सचिव संगठन ने दूध के दाम व हेड लोड बढ़ाने, पशु आहार की दर कम करने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया।धरना प्रदर्शन के चलते दूध सप्लाई को भी बाधित रखा। उच्चाधिकारियों के पहुंचने पर हुई वार्ता के बाद 2 घंटे बाद दूध सप्लाई शुरू हुई।वार्ता में तय हुआ कि एक दिसंबर तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व दूध की सप्लाई रोकने का निर्णय लिया गया।

विकासखंड चौखुटिया के दुग्ध अवशीतन केंद्र जेठुआ भगोती पर चौखुटिया,द्वराहाट, ताड़ीखेत, भिकियासैंण ब्लाकों के दूध उत्पादक, सचिव संगठन के सदस्य भारी तादाद में एकत्रित हुए। तथा धरना प्रदर्शन शुरू कर अल्मोड़ा को होने वाली दूध सप्लाई की गाड़ी को रोक दिया। दूध उत्पादक व सचिव संगठन का कहना है कि अन्य राज्यों में दूध संघ द्वारा दूध खरीद की कीमत बढ़ा दी गई है। उन्होंने 5 रू प्रति लीटर दूध कीमत व हेड लोड दर एक रूपया लीटर प्रति किलोमीटर करने सहित पशु आहार दर में दो रुपया बीस पैसा प्रति किलो हुई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।

धरना प्रदर्शन स्थल पर अल्मोड़ा से प्रभारी जीएम अरुण नगरकोटी व केवलानंद पपनै वार्ता के लिए पहुंचे । जिम्मेदार अधिकारी के नहीं आने पर आंदोलनकारी भड़क गए। काफी बहस के बाद हुई वार्ता में 1 दिसंबर से दूध की कीमत में बढ़ोतरी करने तथा उत्पादकों की अन्य समस्याओं का भी समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक उत्पादकों ने सप्लाई की गाड़ी भी रोकी रही। वार्ता के बाद दूध की सप्लाई गाड़ी को जाने दिया।आंदोलनकारी ने कहा कि 1 दिसंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं होने पर पुनः अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और दूध सप्लाई को बाधित करने का निर्णय लिया गया।

धरना प्रदर्शन में संगठन के अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट,कैलाश चंद्र, सूरज कुमंया, गणेश सिंह नेगी, चंदन सिंह पवार, जगत गोस्वामी, बिशन सिंह आदि मौजूद रहे।

सितारगंज पुलिस ने दो स्मैक तस्करों को दबोचा, 7.97 ग्राम स्मैक बरामद

शक्तिफार्म के रहने वाले हैं दोनों आरोपी, अलग-अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ा

नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई, एनडीपीएस अधिनियम में मुकदमा दर्ज



के.के.पी संवाददाता

सितारगंज (दीपक भारद्वाज)

नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सितारगंज पुलिस ने स्मैक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से कुल 7.97 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक का शुद्ध वजन 7.97 ग्राम बताया गया है। दोनों आरोपी अलग-अलग स्थानों पर पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़े गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में जनपद ऊधमसिंह नगर में नशे के खिलाफ नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सितारगंज कोतवाली पुलिस ने 25 नवंबर को दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध और क्षेत्राधिकारी सितारगंज के पर्यवेक्षण में पुलिस की टीमें संदिग्ध व्यक्तियों और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर नजर रख रही थीं।

पहली कार्रवाई सिडकुल चौकी क्षेत्र में की गई। उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान अंबुजा कंपनी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके कब्जे से 5.70 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जांच में स्मैक का शुद्ध वजन 4.88 ग्राम पाया गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम अभय दास पुत्र निरंजन दास निवासी जेल कैंप नंबर-दो, शक्तिफार्म, सितारगंज बताया। उसकी उम्र 20 वर्ष है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0610/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 में मुकदमा दर्ज किया।

वहीं दूसरी कार्रवाई सितारगंज-अमरिया मार्ग पर इंदर रोड के पास की गई। उपनिरीक्षक दीपक कौशिक पुलिस कर्मियों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3.84 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसका शुद्ध वजन 3.09 ग्राम पाया गया।

एक नजर

संविधान की विकास यात्रा और अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता पर हुई चर्चा

के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना परिसर के इतिहास विभाग में संविधान दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में वक्ताओं ने भारतीय संविधान की विकास यात्रा, सामाजिक समानता और डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों तथा वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य वक्ता डॉ. गोकुल सिंह देउपा ने भारतीय संविधान के क्रमिक विकास और स्वतंत्रता प्राप्ति के कठिन संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने संविधान में निहित समानता के सिद्धांत की महत्ता बताते हुए कहा कि आज डॉ. अंबेडकर के जीवन और विचारों से निरंतर सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आत्ममंथन करने का आह्वान किया कि जिस संघर्ष से देश को आजादी मिली, क्या हम वर्तमान में वास्तव में डॉ. अंबेडकर के दर्शन को जान और अपने जीवन में अपना पा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रवि कुमार ने किया। उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर को ज्ञान का प्रतीक बताते हुए कहा कि वंचित वर्गों के उत्थान, महिलाओं के सशक्तीकरण तथा समान कानून और समान अधिकार की अवधारणाओं के पीछे डॉ. अंबेडकर के दूरदर्शी विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने इन विचारों को संवैधानिक और कानूनी स्वरूप देकर देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। गोष्ठी में डॉ. लक्ष्मी वर्मा, डॉ. शालिनी पाठक, नीरज बिष्ट सहित इतिहास विभाग के छात्र-छात्राएं रेनू लटवाल, दीपा मेहरा, प्रियंका लटवाल, ललित लटवाल, विनय कुमार, अशोक कुमार, अरुण प्रसाद, आदित्य, अंजलि, दिव्या, रिचा, शोभा, निशा, प्रियंका, अंबिका, सुजल, दीपक, हिमांशु, मोनिका आदि उपस्थित रहे।

मतदाता सूची की शुद्धता के लिए अल्मोड़ा में विशेष अभियान, बीएलओ कर रहे जांच

के.के.पी संवाददाता/अल्मोड़ा। विधानसभा निर्वाचक नामावली की शुद्धता सुनिश्चित करने और मतदाताओं की सुविधा के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 20 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 27 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी अपने-अपने मतदेय स्थलों की निर्वाचक नामावली की जांच कर त्रुटियों को चिह्नित कर रहे हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। त्रुटियों के सुधार के लिए संबंधित मतदाताओं से फॉर्म-8 भरवाया जाएगा। वहीं, एक से अधिक बार या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नामों को नियमानुसार फॉर्म-7 के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति का एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों अथवा एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर को हो चुका है। नाम शामिल कराने, हटाने या संशोधन के लिए 11 दिसंबर तक फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं। इनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा और अंतिम निर्वाचक नामावली 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपने और परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम व विवरण जांचने तथा त्रुटि मिलने पर संबंधित बीएलओ के पास आवेदन देने की अपील की है। निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील और संबंधित बीएलओ के पास उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन भी देखा जा सकता है।



संविधान दिवस पर सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में हुआ प्रस्तावना का सामूहिक पाठ, संवैधानिक मूल्यों के पालन की दिलाई शपथ

के.के.पी संवाददाता। संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भारतीय संविधान के महत्व, उसके मूल आदर्शों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने में संविधान की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह बिष्ट ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया। उन्होंने सभी को संविधान में निहित मूल आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप अपने दायित्वों का निष्ठा, निष्पक्षता एवं ईमानदारी से निर्वहन करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने संविधान की गरिमा बनाए रखने तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित भारत की संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य की भावना को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। साथ ही सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

राम के राजतिलक के साथ गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

30 साल बाद लौटी रामलीला की परंपरा, लक्की ड्रा में भरत का अभिनय करने वाले सचिन के नाम निकली स्कूटी





के.के.पी संवाददाता

हरिद्वार। हरिपुर कलां में करीब तीन दशक तक बंद रही रामलीला की परंपरा वर्ष 2025 में दोबारा शुरू होने के बाद लगातार दूसरे वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ आगे बढ़ी। श्री रामलीला कमेटी हरिपुर कलां की ओर से 13 नवंबर से 25 नवंबर तक रामलीला का मंचन किया गया। समापन अवसर पर भगवान श्रीराम का भव्य राजतिलक किया गया। इसके बाद निकले विजय जुलूस में ग्रामीणों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर भगवान श्रीराम का स्वागत किया। जय श्रीराम के जयकारों से पूरा हरिपुर कलां भक्तिमय हो उठा। रामलीला के अंतिम दिन भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और राजतिलक का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत के स्वरूपों का श्रद्धालुओं ने पूजन किया। राजतिलक के बाद रामलीला कमेटी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और रामलीला के कलाकार शामिल हुए। जुलूस के मार्ग में लोगों ने पुष्पवर्षा कर भगवान श्रीराम के स्वरूपों का स्वागत किया। रामलीला के समापन पर कमेटी की ओर से लक्की ड्रा कराया गया। इसमें रामलीला में भरत का अभिनय करने वाले सचिन कुमार के नाम स्कूटी निकली। स्कूटी निकलने पर कलाकारों और कमेटी पदाधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अतिथि ग्राम प्रधान सविता शर्मा और समाजसेवी गुलशन अदलखा ने सचिन कुमार को स्कूटी की चाबी भेंट की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

इसके बाद रामलीला में विभिन्न पात्रों का अभिनय करने वाले कलाकारों को पुरस्कार और उपहार देकर सम्मानित किया गया। कमेटी की ओर से कलाकारों के बेहतर अभिनय और मेहनत की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया।

श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि करीब 30 साल के अंतराल के बाद वर्ष 2025 में हरिपुर कलां में रामलीला की परंपरा को दोबारा शुरू किया गया था। लगातार दूसरे वर्ष रामलीला का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि रामलीला केवल धार्मिक मंचन नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और संस्कारों से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने बताया कि रामलीला में अभिनय करने वाले सभी कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमेटी की ओर से एक सप्ताह के भीतर पांच लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कलाकार पूरे उत्साह और मेहनत के साथ अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। उनके उत्साहवर्धन के लिए कमेटी की ओर से उपहार और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अतिथि गुलशन अदलखा ने कहा कि करीब 30 वर्ष बाद हरिपुर कलां में रामलीला की परंपरा का दोबारा शुरू होना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। रामलीला के माध्यम से बच्चों और युवाओं को भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और भगवान श्रीराम के आदर्शों से जुड़ने का अवसर मिल रहा है।

अल्मोड़ा में कांग्रेस को मिली नई ताकत, पूर्व आप नेता अमित जोशी ने थामा कांग्रेस का दामन,देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता, अल्मोड़ा विधायक सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे मौजूद



के.के.पी संवाददाता

अल्मोड़ा/देहरादून- अल्मोड़ा विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक पद का चुनाव लड़ चुके,आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश पदाधिकारी एवं शिक्षाविद अमित जोशी ने गुरुवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया।देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।अमित जोशी के कांग्रेस में शामिल होने को अल्मोड़ा की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।शिक्षाविद के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अमित जोशी पूर्व में आम आदमी पार्टी में प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं।इसके साथ ही वह अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं।ऐसे में उनके कांग्रेस में शामिल होने से जिले की राजनीतिक गतिविधियों में नई चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस की नीतियों एवं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर अमित जोशी कांग्रेस में शामिल हुए हैं।कांग्रेस में शामिल होने के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल,वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं विधायक प्रीतम सिंह,पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की मौजूदगी में हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम को कांग्रेस के लिए अहम माना जा रहा है।अमित जोशी के पार्टी में आने से अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी।वहीं इस घटनाक्रम के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।

57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल में मनाया गया संविधान दिवस

अधिकारियों और जवानों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कर ली शपथ



के.के.पी संवाददाता

सितारगंज,(दीपक भारद्वाज)

57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, सितारगंज में गुरुवार को संविधान दिवस हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक कमांडेंट जसवीर सिंह के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाहिनी के अधिकारियों एवं जवानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान कार्यवाहक कमांडेंट जसवीर सिंह ने उपस्थित अधिकारियों और जवानों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया। इसके साथ ही सभी को संविधान के प्रति निष्ठा एवं सम्मान बनाए रखने तथा उसमें निहित मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की शपथ दिलाई गई।

इस दौरान कार्यवाहक कमांडेंट जसवीर सिंह ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है। इसमें निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को दर्शाते हैं।

प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से सुरक्षा बलों के जवानों का दायित्व है कि वे इन संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ करें।

उन्होंने जवानों को राष्ट्र की सेवा के साथ-साथ संविधान में दिए गए आदर्शों और मूल सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों एवं जवानों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी की भावना को और अधिक मजबूत करना रहा।

इस अवसर पर वाहिनी के अधिकारियों एवं जवानों ने संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने का संकल्प लिया।

पाकिस्तान में लापता हो रही लड़कियां और महिलाएं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

सिर्फ पंजाब में 500 से अधिक मामले

कराची। पाकिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के रहस्यमय ढंग से लापता होने का संकट गहराता जा रहा है, खासकर पंजाब प्रांत में, जहां हजारों की संख्या में शिकायतें दर्ज हुई हैं। इन मामलों में पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर लाहौर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जाहिर की है, जिसके बाद ही प्रशासन हरकत में आया है। पुलिस और अदालती रिपोर्टों से सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जो देश में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में पंजाब के पुलिस प्रमुख ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि सिर्फ पंजाब में 500 से अधिक मामले अब भी लंबित हैं। यह खुलासा तब हुआ जब याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। रिपोर्टों के अनुसार, साल 2021 से 2025 के बीच महिलाओं के अपहरण के कुल 3,258 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 2,871 को बरामद किया गया, लेकिन 387 महिलाएं आज भी लापता हैं। इसमें से कई का सालों बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिवारों का दर्द बढ़ता जा रहा है।

लापता महिलाओं में से 221 मामले जबरन शादी या अवैध संबंधों के लिए अपहरण से संबंधित पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 365-बी के तहत दर्ज हैं, जबकि 166 मामले गलत इरादे से बहला-फुसलाकर ले जाने से जुड़ी धारा 496-ए के तहत हैं। सालवार आंकड़ों के मुताबिक 2025 में 130 महिलाएं, 2024 में 98, 2023 में 66, 2022 में 47 और 2021 में 46 महिलाएं अभी भी लापता हैं।

बांग्लादेश आज अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर अहम मोड़ पर खड़ा

हसीना की वापसी से मुजीब की धर्मनिरपेक्ष विरासत को मिल सकती मजबूती



ढाका। बांग्लादेश आज अपनी राष्ट्रीय पहचान को लेकर अहम मोड़ पर खड़ा है, जहां शेख मुजीबुर रहमान के बंगाली राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा का टकराव राजनीतिक कट्टरपंथी ताकतों से हो रहा है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद यह टकराव और गहरा गया और अब दिसंबर 2026 में उनकी संभावित वापसी को मुजीब की विरासत की वापसी और कट्टरपंथी शक्तियों के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

भारत और बांग्लादेश के बीच उनके प्रत्यर्पण का मुद्दा भी इसी कानूनी और राजनयिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। हसीना की वापसी से अवामी लीग की राजनीतिक जगह और मुजीब की धर्मनिरपेक्ष विरासत को मजबूती मिल सकती है। बांग्लादेश के सामने राजनीतिक कट्टरवाद और हिंसा चुनौती बनी हुई है। जानकारों के मुताबिक यह टकराव बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और राष्ट्रीय एकता के लिए निर्णायक होगा। बता दें बांग्लादेश का जन्म 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर अपनी भाषा, संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष पहचान को बचाने के संघर्ष के परिणामस्वरूप हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 1972 में देश का संविधान राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के चार मूल सिद्धांतों पर आधारित था, जिसमें बंगाली राष्ट्रवाद को भाषा और संस्कृति से जोड़ा गया था। हालांकि, 1975 में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद, सैन्य शासनों ने संविधान में बदलाव किए, धर्मनिरपेक्षता को हटाकर धार्मिक संदर्भ जोड़े और इस्लाम को राज्य धर्म घोषित किया। 2011 में धर्मनिरपेक्षता को फिर से शामिल किया गया, लेकिन इस्लाम का राज्य धर्म का दर्जा बरकरार रहा, जिससे एक विरोधाभासी स्थिति बनी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद हसीना के सत्ता से हटने से बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। मुजीब के स्मारकों और प्रतीकों पर हमले हुए, जबकि जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों को फिर से राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होने का अवसर मिला। अंतरिम सरकार ने जमात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, जिससे उसके छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर ने भी विश्वविद्यालयों में अपनी सक्रियता बढ़ाई। इस दौरान अल्पसंख्यकों और सूफी दरगाहों पर हमलों की कई खबरें भी सामने आईं, जो देश में बढ़ती धार्मिक कट्टरता का संकेत थीं।

हम मरेंगे तो कुछ करके मरेंगे... सपा के घोषणापत्र से पहले आजम खान का बड़ा बयान



लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत तेज है। गठबंधन को लेकर सपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। खींचतान जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी अपना घोषणापत्र जारी कर दी। इस दौरान आजम खान ने अपने बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत मुश्किल समय से गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त जान साबित हुए हैं। हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे।

आजम खान ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ करके ही मरेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वे बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, फिर भी मजबूत बने रहे। उन्होंने कहा कि हम बहुत सख्त जान साबित हुए हैं। हम मरेंगे तो, लेकिन कुछ बड़ा जरूर करेंगे।

आजम खान ने आगे कहा कि रास्ते तो तय होते हैं, लेकिन मंजिल तय नहीं होती। लोग घाटे का सौदा नहीं करते, लेकिन हम उन कुछ बेवकूफ लोगों में से हैं जो ऐसा करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के परिवार में अपने जीवन के 50 साल बिताए हैं।

अपनी जेल की यातनाओं का जिक्र करते हुए आजम खान ने भावुक होते हुए कहा कि मेरे साथ जो हुआ, वह अंग्रेजों ने भी नहीं किया। मुझे एक बेगुनाह बेटे के साथ जेल में डाल दिया गया। हम दर्द का बहता हुआ समंदर हैं। हम वोट काटने वाले नहीं हैं, हम वोट जोड़ने वाले हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जेल में रहते हुए कई बार उनका मन करता था कि अखिलेश यादव भी छह महीने के लिए जेल आ जाएं। तभी उन्हें असली मायने में पता चलेगा कि जेल में दिन कैसे कटते हैं और रातें कैसे बीतती हैं। आजम खान ने कहा कि बिना जेल की सजा झेले कोई भी इंसान उस दर्द को नहीं समझ सकता।

रामपुर की एक पुरानी कहानी सुनाते हुए आजम खान ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ दूसरों का खेल बिगाड़ना होता है। वे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। उनकी बात साफ तौर पर कांग्रेस की ओर इशारा कर रही थी।

इस दौरान रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कद को जरूरत से कहीं ज्यादा बढ़ा लिया है। उनका असली मकसद सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार न बनने दी जाए। आजम खान ने साफ कहा कि कांग्रेस का खेल सिर्फ बिगाड़ना है।

उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक) का जो प्रणपत्र (घोषणापत्र) है, उसमें जो बातें लिखी नहीं हैं, वे भी सरकार बनने के बाद जरूर पूरी की जाएंगी।

बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को फिर जेल जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का फैसला पलटा



नई दिल्लीः गोपालगंज के तत्कालीन ष्ठरू जी. कृष्णैया की 1994 में हुई मॉब लिंचिंग और हत्या के मामले में दोषी पूर्व सांसद आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मोहन को समय पूर्व रिहाई का फैसला पलट दिया है. कोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए कानून और नैतिकता का पक्ष लेना जरूरी है. कोर्ट ने कहा कि वो मूकदर्शक बने नहीं रह सकती है. कोर्ट ने एक महीने के भीतर मोहन को सरेंडर करने का दिया आदेश.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार का आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई के फैसले को पलटते हुए कहा कि रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए अदालत का दायित्व है कि वह सक्रिय रूप से न्याय सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा केवल निगरानी की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि मनमानी कार्रवाई के खिलाफ वैधानिकता, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने का सक्रिय माध्यम है. गोपालगंज जिलाधिकारी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की सजा में छूट की नई प्रक्रिया तभी शुरू हो सकेगी, जब वह एक महीने के भीतर आत्मसमर्पण करेंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि बिहार सरकार पूर्व सांसद आनंद मोहन की सजा में छूट के लिए स्वतंत्र, लेकिन उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा.

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने जी कृष्णैया की विधवा की बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका दाखिल करने की भी इजाजत दी. कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में प्रिजन मैन्युल में बदलाव का फैसला गैर संवैधानिक था.

'मैं इंडिया से हूं' कहकर कराची में घूमने लगा यूट्यूबर, बोला- एकदम बदल गया लोगों का व्यवहार



नई दिल्ली। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर राहुल राठौड़ ने कराची की सड़कों पर खुद को 'भारतीय' बताया. उसका मकसद यह जानना था कि आम पाकिस्तानी भारत के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं. कराची के बाजारों में कदम रखते ही नफरत के सारे दावे हवा हो गए. खाने-पीने के दुकानदारों ने उन्हें भारत का मेहमान बताकर पैसे लेने से इनकार कर दिया, तो कपड़ा और जूता व्यापारियों ने भी भारी डिस्काउंट दिया. यूट्यूबर ने अपने एक्सपीरियंस में कहा कि पाकिस्तानियों ने असल चेहरा दिखा दिया. जो मीडिया में नहीं दिखाया जाता. इस अनुभव का पूरा वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है.

कराची की भागती-दौड़ती जिंदगी के बीच यूट्यूबर राहुल जब 'हसन कचोरी हाउस' पहुंचे, तो वहां गरमा-गरम समोसे और कचोरियां छन रही थीं. दुकानदार को जैसे ही पता चला कि सामने खड़ा शख्स सरहद पार भारत से आया है, उसने तपाक से कहा, 'आप तो हमारे मेहमान हैं, आपके लिए सब फ्री है, मोहब्बत में जो मर्जी खाओ.' थोड़ा आगे बढ़े तो 50 पाकिस्तानी रुपए का गन्ने का जूस बेचने वाले भाई ने भी हाथ जोड़ लिए और पैसे लेने से साफ मना कर दिया. यही नहीं, 100 रुपए की कचोरी-छोले की चाट बेचने वाले चाचा ने भी मुस्कुराकर कहा, 'पैसों की कोई कमी नहीं है बेटा, पर आप इतनी दूर से आए हो, हमारे मेहमान हो.

खाने-पीने के बाद जब व्लॉगर कपड़ों और जूतों के बाजार में पहुंचे. जींस-ट्राउजर की दुकान पर 1200 रुपए का ट्राउजर दुकानदार ने भारत के नाम पर 800 में देने की पेशकश की और कहा, 'भारत भी तो हमारा भाई है यार.

अपने दुश्मन चीन को क्लीनचिट देने के लिए क्यों बेताब हुए ट्रंप?



नई दिल्ली। AI की दुनिया में लगातार हलचल मची हुई है. अफेयर की वजह से चिप्स सप्लाई करने वाली पावरफुल कंपनी Nvidia के सह-संस्थापक Jensen Huang को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी. ये भी आरोप था कि महिला चीनी जासूस है. लेकिन, अब Jensen Huang की वापसी हो गई है. और इसके लिए अमेरिका ने पूरा जोर लगा दिया. अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है.

Jensen Huang की दोबारा बहाली को लेकर अमेरिका में एक बहुत बड़ा राजनीतिक और रक्षा विवाद खड़ा हो गया है. वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने Nvidia कंपनी को Jensen Huang को वापस सीईओ पद पर नियुक्त करने के लिए कॉल्ड वार के जमाने के एक बेहद खतरनाक सैन्य कानून 'डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट' (DPA) का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी कर ली थी. आपको बता दें कि ये कानून राष्ट्रपति को युद्ध जैसी आपातकालीन स्थितियों में किसी भी निजी कंपनी के ऊपर सीधे कब्जा करने या उसकी पूरी परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन को राष्ट्रीय सुरक्षा के कामों में डायवर्ट करने की ताकत देता है.

डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में Hegseth और उनके करीबियों का प्लान इस सैन्य कानून को Nvidia के खिलाफ एक दबाव बनाने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल करना था. इंटरनल सोर्स के हवाले से रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पेंटागन ने Nvidia को चेतावनी दी थी कि अगर वो Jensen Huang को वापस नहीं लाते, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर DPA कानून लागू कर देंगे. इसके तहत Nvidia को अपने कमर्शियल सुपर-चिप्स का प्रोडक्शन पूरी तरह बंद करके अमेरिकी सेना के लिए मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पर काम करना पड़ता. ऐसा होने से Nvidia की सेल और प्रॉफिट को भारी नुकसान पहुंचता. इसी डर से Nvidia के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ट्रंप की बात मानने के लिए तुरंत मजबूर हो जाते.

मल्लिकार्जुन खरगे ने दी इमरान मसूद को नसीहत, बोले- सिर्फ बातों पर नहीं, काम पर दें ज्यादा ध्यान



लखनऊ। यूपी विधानसभा से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है. इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं. इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपनी बयानबाजी के लिए इमरान मसूद को सार्वजनिक मंच से हिदायत दी है. खरगे ने कहा कि हमें सिर्फ बातों के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए. जितना ज्यादा मिलकर काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे.

लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'इमरान मसूद को मैं अक्सर टेलीविजन पर सुनता हूं, जहां वे बहुत जोश के साथ अपनी बात रखते हैं. हालांकि हमें सिर्फ बातों के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए. हम जितना ज्यादा मिलकर काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे. वे संसद में हैं, जहां वे लगातार पार्टी के लिए लड़ते हैं और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हमारी बातों और स्टैंड को मजबूती से रखा जाए.'

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं होने वाली है. हमारा 143 साल पुराना इतिहास है. अगर कांग्रेस पार्टी 143 सालों में खत्म नहीं हुई, तो अब क्यों खत्म होगी? हमारे पास अब एक ऐसा नेता है जो किसी से नहीं डरता और जिसे कोई डरा भी नहीं सकता. हम ऐसे लोग नहीं हैं जो डरकर जीते हैं. हो सकता है कि डर की वजह से कुछ लोग बीजेपी में शामिल हो जाएं या अपने घरों में बैठ जाएं. लेकिन हम जिन्होंने इस संविधान को बनाने में मदद की, इसकी रक्षा करेंगे. हम किसी से नहीं डरेंगे. आरएसएस इस संविधान के खिलाफ था.वे तब भी इसके खिलाफ थे और आज भी संविधान का विरोध करते हैं. इसलिए आज दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है.

2027 चुनाव से पहले यूपी पुलिस में 183 इंस्पेक्टरों के ताबड़तोड़ तबादले; लखनऊ, नोएडा और कानपुर में बड़ा फेरबदल



लखनऊः आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. पुलिस स्थापना बोर्ड की संस्तुति और अनुमोदन के बाद प्रदेशभर में 183 निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) के तबादले किए गए हैं. इस कार्रवाई के तहत एक ही जिले में लंबे समय से तैनात अधिकारियों को दूसरे जिलों और कमिश्नरेट में भेजा गया है. सबसे ज्यादा तबादले लखनऊ कमिश्नरेट से हुए हैं, जहां से 56 निरीक्षकों को स्थानांतरित किया गया है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश की लिस्ट के अनुसार यह तबादले विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों और निर्वाचन आयोग के मानकों को ध्यान में रखकर किए गए हैं. निर्णय उन निरीक्षकों पर लागू किया गया है, जिन्होंने एक ही जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है या 31 मई 2027 तक पिछले चार वर्षों में तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेंगे.

पुलिस मुख्यालय का मानना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों का स्थानांतरण चुनावी निष्पक्षता और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है. तबादला आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किए गए हैं. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कमिश्नरेटों में समायोजन संभव नहीं होने और पुलिस आयुक्तों की ओर से अन्यत्र स्थानांतरण के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया.

एलियंस की दुनिया में इंसानों का डेटा, Elon Musk आखिर अब क्या बवाल करने वाले हैं?



नई दिल्ली। Elon Musk की अंतरिक्ष कंपनी SpaceX ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो कल तक केवल साइंस-फिक्शन फिल्मों में ही देखने को मिलता था. अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) ने SpaceX को अंतरिक्ष में ऑर्बिटिंग डेटा सेंटर्स बनाने के अपने प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख सैटेलाइट्स लॉन्च करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि पिछले एक साल में अंतरिक्ष में क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स स्थापित करने की होड़ बहुत तेजी से बढ़ी है. इस रेस में केवल SpaceX ही नहीं, बल्कि दुनिया की अन्य दिग्गज टेक कंपनियां भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं.

इस स्पेस रेस की बात करें तो SpaceX के इस खास प्रोजेक्ट को Starmind कॉन्स्टेलेशन नाम दिया गया है. इसके मुकाबले में Google भी चुपके से 'Suncatcher' कोडनेम के तहत अपने स्पेस डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि जेफ बेजोस की कंपनी Blue Origin ने भी एफसीसी के पास अपने 'प्रोजेक्ट सनराइज' के लिए आवेदन जमा कर दिया है. इनके अलावा कई नए स्टार्टअप्स भी इस रेस में शामिल हैं, जिनमें स्टारक्लाउड नाम का स्टार्टअप सबसे आगे है. जिसने साल 2025 के अंत में एक सैटेलाइट के ऊपर कंप्यूटर के सबसे एडवांस प्रोसेसर यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक चलाकर इतिहास रच दिया था. गूगल ने भी इसी साल अक्टूबर में ये सफलता हासिल की है.

एफसीसी की वेबसाइट पर पब्लिश किए गए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, SpaceX को सैटेलाइट्स लॉन्च करने की ये बड़ी मंजूरी पूरे साल 2040 तक के लिए दी गई है. इस प्रोजेक्ट में SpaceX के पास सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके पास खुद के पावरफुल फॉल्कन रॉकेट्स मौजूद हैं. ये पहले ही सैकड़ों सफल स्पेस मिशन्स को पूरा कर चुके हैं, जिससे उनके लिए लॉन्चिंग का खर्च बाकी कंपनियों के मुकाबले बेहद कम होने वाला है. SpaceX के मालिक Elon Musk ने बताया है कि वो साल 2027 की आखिरी तिमाही (Q4 2027) तक इस ऑर्बिटिंग डेटा सेंटर के पहले सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर देंगे, और साल 2028 से इसकी लॉन्चिंग की रफ्तार को कई गुना तेज कर दिया जाएगा. इस ऐतिहासिक काम के लिए SpaceX ने दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनी Nvidia के साथ एक बहुत बड़ी डील की है.

संजय कपूर संपत्ति विवाद

15 मुलाकातों में भी नहीं सुलझा कपूर फैमिली का झगड़ा, SC 6 हजार करोड़ की प्रापर्टी पर लेगा फैसला



दिल्लीः बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर का प्रॉपर्टी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है. इसे लेकर कानूनी लड़ाई लगातार जारी है. संजय कपूर की संपत्ति और फैमिली ट्रस्ट को लेकर उनकी मां रानी कपूर और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई.रानी कपूर की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि उनकी मुवक्किल फैमिली ट्रस्ट में अपना हिस्सा मांग रही हैं और उनका दावा करीब 6,000 करोड़ रुपये का है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल किया कि आखिर रानी कपूर का दावा क्या है और वह कितनी रकम मांग रही हैं? इस पर दवे ने बताया कि वह ट्रस्ट की संपत्ति में अपना हिस्सा चाहती हैं और उनकी मांग लगभग 6,000 करोड़ रुपये की है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि यदि रानी कपूर को इतनी बड़ी रकम दी जानी है तो ट्रस्ट की संपत्तियों का परिसमापन (Liquidation) कौन करेगा और भुगतान किस तरह किया जाएगा? अदालत ने दोनों पक्षों से लचीला रुख अपनाने की अपील की.पीठ ने टिप्पणी की कि रानी कपूर लड़ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि बाकी सभी लोग भी क्यों लड़ रहे हैं?

अदालत ने कहा कि अब तक मध्यस्थता की 15 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है. रानी कपूर की ओर से सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनकी तरफ से समझौते का प्रस्ताव दिया गया था. इसके बाद छह महीने तक दूसरे पक्ष के जवाब या प्रति-प्रस्ताव का इंतजार किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया. इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 15 बैठकों के बावजूद, दोनों पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए.

संविधान दिवस पर यूथ के साथ 'वैलेंटाइन डे' मनाना चाहती है बीजेपी

नई दिल्ली। देश भर में आज यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं से जुड़ने के लिए एक नया अभियान शुरू करने की योजना बनाई है. जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर 'संविधान रक्षा' मार्च निकालने का ऐलान किया है. बीजेपी की योजना के मुताबिक, संविधान दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में स्पेशल कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्टी नेतृत्व ने अपने सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को निर्देश दिया है कि वे 26 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों का आयोजन करें और युवाओं से संवाद करें. वहीं दूसरी तरफ, कांग्रेस भी संविधान दिवस के मौके पर अपना राजनीतिक अभियान तेज कर रही है. कांग्रेस का कहना है कि संविधान रक्षा मार्च कथित वोट चोरी के मुद्दे के विरोध में आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक मूल्यों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने लेख में आरोप लगाया कि देश के इतिहास में कई बार संविधान को कमजोर करने का काम उन्हीं लोगों ने किया, जिन पर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी. पीएम मोदी ने आर्टिकल 356 के कथित दुरुपयोग, आपातकाल और विभिन्न संवैधानिक संशोधनों का जिक्र करते हुए कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.

ग्रह के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे दो अंतरिक्ष यान

वाशिंगटन। यूरोप और जापान का संयुक्त मिशन बेपीकोलंबो अब सौरमंडल के सबसे छोटे और सूर्य के सबसे करीब स्थित इस रहस्यमयी ग्रह के अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। आठ साल की लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पूरी करने के बाद दो अंतरिक्ष यान अब बुध ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं। इन अंतरिक्ष यानों ने छह अरब मील से ज्यादा का सफर तय किया है। बुध ग्रह, जहां सूर्य की प्रचंड गर्मी तापमान को 427 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचा देती है, वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से एक पहेली रहा है। उसके कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं, जिन्हें जानने के लिए इतने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है। दोनों रोबोटिक यान अगले महीने एक-दूसरे से अलग होकर बुध की सतह, उसके चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना का अलग-अलग ऊंचाइयों से विस्तृत अध्ययन करेंगे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से बेपीकोलंबो के बुध ग्रह पर पहुंचने की पुष्टि की। प्रणोदक को कई बार चालू करके अंतरिक्ष यान की गति को धीरे-धीरे कम किया गया ताकि बुध का कमजोर गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी कक्षा में खींच सके।

हालांकि, जर्मनी में बैठे उड़ान नियंत्रकों को इस बात की पुष्टि करने में कई घंटे लग गए कि बेपीकोलंबो बुध की कक्षा में पहुंच चुका है, क्योंकि वे ग्रह से 9.4 करोड़ मील दूर थे। यह इतिहास में तीसरा ऐसा मिशन है जो बुध ग्रह तक पहुंचा है। इससे पहले, 1970 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मैरिनर-10 तीन बार बुध के पास से गुजरा था, और फिर 2011 में नासा का ही मैसेंजर यान बुध की कक्षा में पहुंचा था, जो 2015 में ईंधन खत्म होने के बाद ग्रह से टकराकर नष्ट हो गया था। बेपीकोलंबो मिशन का नाम दिवंगत इतालवी गणितज्ञ बेपी कोलंबो के नाम पर रखा गया है, जो मैरिनर-10 टीम का हिस्सा थे। वर्ष 2018 में प्रक्षेपित, बेपीकोलंबो ने बुध तक पहुंचने के लिए एक लंबा और घुमावदार रास्ता चुना।

इस दौरान इसने एक बार पृथ्वी, दो बार शुक्र और छह बार स्वयं बुध ग्रह के पास से गुजरकर उनके गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल अपनी दिशा और गति बदलने में किया।

स्वामी/ प्रकाशक / मुद्रक
प्रमोद कुमार ने जय माँ गंगा प्रिंटर्स, हरिद्वार से मुद्रित कराकर कार्तिकेय कॉलोनी, फेस-3, दर्पण स्कूल वाली गली, निकट हनुमान मंदिर, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी जनपद-नैनीताल (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादक
प्रमोद कुमार
मो.7830201066
सह-सम्पादक
दया जोशी
मो.9412135616